04 - झारखंड छात्र आंदोलन में सीबीआई जांच न करवाने के मायने

05 - ऊर्जा आत्मनिर्भरता की राह पर बढ़ता भारत

A Daily News Magazine

इंदौर

गुरुवार, 20 अगस्त, 2026

06 - नई पीढ़ी बनाम पुरानी पीढ़ीः एक नजरिया यह भी

07 - राजगढ़ हत्याकाण्ड में नया मोड़ ASI के समर्थन में आए पूर्व...

इंदौर एवं भोपाल से एक साथ प्रकाशित

वर्ष 11 अंक 318, नगर संस्करण, पृष्ठ 8, मूल्य रू. 2

प्रसंगवश

बीजेपी की नई टीम में यूपी के लिए क्या संदेश है?

प्रेरणा

बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन की नई टीम के बैकग्राउंड से लेकर राज्य की राजनीति में उसके प्रभाव का आकलन और विश्लेषण किया जा रहा है। क्योंकि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में महज़ छह महीने का वक्त बचा है और ये भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा चुनावी मैदान भी है। लोकसभा की 80 सीटों के साथ देश की कुल 543 सीटों में अकेले यूपी की हिस्सेदारी क़रीब 15 फ़ीसदी है। 2027 का विधानसभा चुनाव सिर्फ़ लखनऊ की सत्ता का मुकाबला नहीं होगा, इसके नतीजे 2029 की राष्ट्रीय राजनीति के लिए भी संकेत देने वाले माने जाएंगे।

यही कारण है कि नितिन नबीन की टीम में शामिल पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, जो कि मूलतः उत्तर प्रदेश की हैं नहीं, पर उनकी राजनीतिक ज़मीन यही हैं। उनके अलावा नई टीम में बस्ती से दो बार के सांसद रहे हरीश द्विवेदी, धौरहरा सीट से सांसद रहीं रेखा वर्मा, राज्यसभा सांसद संगीता यादव और अमरपाल मौर्य, बुलंदशहर के सांसद डॉ. भोला सिंह, पूर्व अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कुलपति तारिक़ मंसूर और बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष कुंवर बासित अली शामिल किए गए हैं।

इन आठ नामों के अलावा महाराष्ट्र के नेता विनोद तावड़े की भी चर्चा है, जिन्हें उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया है। वहीं, प्रतापगढ़ के डॉ. स्वदेश सिंह को पार्टी का राष्ट्रीय मंत्री बनाया गया है। उन्हें संगठन में युवा प्रतिनिधित्व के तौर पर देखा जा रहा है।

प्रमुख आठ नामों पर नज़र डालें तो पार्टी की तरफ़ से इनके ज़रिए महिलाओं से लेकर ओबीसी, दलित, ब्राह्मण और मुस्लिम समुदायों तक, अलग-अलग सामाजिक समूहों को प्रतिनिधित्व देने की कोशिश दिखती है।

लेकिन बीजेपी इसे किसी चुनावी या विपक्षी रणनीति के जवाब के तौर पर देखने से इनकार करती है। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी कहते हैं कि बीजेपी की राष्ट्रीय टीम किसी क्षेत्रीय दल के नैरेटिव को काउंटर करने के लिए नहीं बनती है। उत्तर प्रदेश राजनीतिक तौर पर बहुत महत्वपूर्ण राज्य है। सबसे ज्यादा लोकसभा की 80 सीटें यहीं से आती हैं। इस लिहाज से उत्तर प्रदेश की भूमिका बड़ी है और उसी अनुपात में राष्ट्रीय टीम में उत्तर प्रदेश को भागीदारी मिली है। लेकिन चुनाव से पहले नई टीम की घोषणा से कार्यकर्ताओं में उत्साह ज़रूर पैदा होता है।'

वरिष्ठ पत्रकार आनंद राय के मुताबिक बीजेपी की नई राष्ट्रीय टीम में यूपी से शामिल किए गए प्रमुख संगठनात्मक चेहरों को सिर्फ़ व्यक्तिगत नियुक्तियों के तौर पर नहीं देखना चाहिए। इनमें क्षेत्रीय, जातीय और महिला प्रतिनिधित्व का संतुलन साधने की कोशिश छुपी है। यूपी को बीजेपी ने संगठनात्मक रूप से छह क्षेत्रों में बांटा है- काशी, गोरखपुर, अवध, कानपुर-बुंदेलखंड, ब्रज और पश्चिम क्षेत्र। नई टीम में शामिल चेहरे इन्हीं अलग-अलग क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

स्मृति ईरानी अवध क्षेत्र से, हरीश द्विवेदी पूर्वी यूपी/गोरखपुर क्षेत्र से, जबकि रेखा वर्मा रुहेलखंड क्षेत्र से आती हैं। इस तरह नियुक्तियों में क्षेत्रीय संतुलन का भी ध्यान रखा गया है। आनंद कहते हैं, ''हरीश जी संगठन के आदमी हैं। दो बार लोकसभा सांसद रह चुके द्विवेदी 2024 में चुनाव हार गए थे, लेकिन पार्टी ने इसके बावजूद उन्हें राष्ट्रीय महामंत्री की महत्वपूर्ण ज़िम्मेदारी दी है। इसके पीछे एक बड़ी वजह उनका ब्राह्मण समाज से आना और अपेक्षाकृत युवा चेहरे को आगे बढ़ाने की कोशिश के रूप में देखा जा सकता है।''

हरीश द्विवेदी संगठन में राष्ट्रीय महामंत्री का पद मिलने पर वह कहते हैं, ''भाजपा कैडर आधारित पार्टी है और जो भी दायित्व पार्टी देती है, वह कार्यकर्ताओं की योग्यता और क्षमता को देखते हुए ही दी जाती है। मुझ पर संगठन का लगातार आशीर्वाद रहा है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव पिछले कुछ वर्षों में कई मौकों पर बीजेपी और योगी आदित्यनाथ सरकार पर ब्राह्मण विरोधी होने के आरोप लगाते रहे हैं। 2020 में विकास दुबे एनकाउंटर के बाद उन्होंने इसे ब्राह्मणों के बीच बढ़ती असुरक्षा और कथित भेदभाव के नैरेटिव से जोड़ा। इसके बाद परशुराम जयंती की छुट्टी खत्म किए जाने और ब्राह्मणों की राजनीतिक हिस्सेदारी जैसे मुद्दों को भी उन्होंने उठाया। अब 2026 में अखिलेश ने अपने 'पीडीए' फॉर्मूले में 'पी' को 'पिछड़ा' और 'पीड़ित' के साथ 'पंडित' से जोड़ते हुए कहा है कि यूपी में ब्राह्मण 'पीड़ा' में हैं।

इस नैरेटिव को लेकर बीजेपी के भीतर भी चिंता के संकेत दिखे हैं। 2020-21 में पार्टी के नेताओं ने ब्राह्मणों के बीच नाराज़गी की धारणा पर चर्चा की थी, और हाल के महीनों में ब्राह्मण विधायकों की अलग बैठक और समुदाय को लेकर बढ़ती राजनीतिक हलचल ने पार्टी नेतृत्व को सतर्क किया है। हालांकि, बीजेपी के भीतर यह भी तर्क है कि संगठन और सरकार में ब्राह्मणों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिला है।

हरीश द्विवेदी कहते हैं, '' ब्राह्मण समाज हो या कोई दूसरा समाज वर्तमान समय में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सभी बीजेपी के साथ हैं।'' लेकिन वरिष्ठ पत्रकार आनंद राय कहते हैं, '' 2024 में पीडीए के ज़रिए सपा को मिली सफलता ने विपक्ष का मनोबल बढ़ाया है। कांग्रेस और सपा 2027 में साथ लड़ने की तैयारी में दिख रहे हैं और 2024 के लोकसभा चुनाव में मिली सफलता उन्हें इस गठबंधन को जारी रखने के लिए प्रेरित करती है। ऐसे में बीजेपी की नई टीम को पीडीए के जवाब में अपना सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन मजबूत करने की कोशिश के तौर पर भी देखा जा सकता है।''

उधर तारिक़ मंसूर और कुंवर बासित अली को संगठन में अहम ज़िम्मेदारी देकर बीजेपी ने पसमांदा मुसलमानों के बीच अपनी पहुंच बढ़ाने की कोशिश का संकेत दिया है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलपति मंसूर पहले से ही बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे और नई टीम में उन्हें इसी पद पर बरकरार रखा गया है। वहीं, कुंवर बासित अली बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चे के अध्यक्ष हैं और उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर भी जिम्मेदारी दी गई है।

आनंद राय कहते हैं, 'बीजेपी को उम्मीद है कि उसकी कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थी वर्ग में शामिल पसमांदा मुसलमानों के बीच पार्टी अपनी जगह बना सकती है। यह कोशिश राष्ट्रीय स्तर पर ही नज़र आती है। राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री केवल हिंदुत्व की राजनीति करने पर ज़ोर देते हैं। ऐसे में संगठन के इस दांव का कुछ ख़ास असर आने की उम्मीद नहीं दिखाई देती।''

बात स्मृति ईरानी की करें तो वरिष्ठ पत्रकार शरत प्रधान कहते हैं कि वह बीजेपी की प्रमुख महिला नेताओं में हैं और एक अच्छी वक्ता भी। ईरानी और योगी आदित्यनाथ, दोनों ही प्रभावशाली और आक्रामक नेता हैं, इसलिए यूपी में उनके बीच समन्वय आसान नहीं होगा।

(बीबीसी हिंदी में प्रकाशित लेख के संपादित अंश)

सुबह सवेरे

subahsaverenews@gmail.com

facebook.com/subahsaverenews

www.subahsavere.news

twitter.com/subahsaverenews

सुप्रभात

बाहर की ओर तो मृत्यु थी
जीवन तो भीतर की ओर था
भीतर की ओर कही गई बात
भीतर की ओर भींची गई मुट्ठी
भीतर की ओर से बंद किवाड़
भीतर की ओर मृत्युरोग
भीतर का लोहा, लहु और धार
इतना सब जीवन जीने के लिए यथेष्ठ था
मैं भीतर की ओर के दृश्य से
ही पहचानी जाऊँ
कतई न पहचानी जाऊँ बाहर के
वस्त्र और वस्तुओं से
मैं भीतर की समग्रता से दुर्घनाग्रस्त होऊँ
बाहर की ओर मात्र जीवन जिऊँ
भीतर की ओर ही मुड़ू, झरूँ, गिरूँ
मरूँ तो भीतर की ओर होकर ही मरूँ
घुटने नाक से चिपकाये
बाहर की ओर चीत्कार करके न मरूँ
मैं दोनों हाथों में बाहर से मिला विष थामे
भीतर के अनिमेष के प्रेम में हूँ।
भीतर की ओर।

- जोशना बनर्जी

रेलवे से हाईवे तक...होगा विस्तार

मोदी कैबिनेट ने पांच बड़ी परियोजनाओं को दी मंजूरी

- 13041 करोड़ रुपये के रेल-रोड प्रोजेक्ट किए गए मंजूर
- हावड़ा-चेन्नई रूट पर बढ़ेंगी लाइनें, बिहार को मिला तोहफा

नई दिल्ली (एजेंसी)। केंद्र सरकार ने देश में रेल और सड़क कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए बड़ा फैसला लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कुल 13,041 करोड़ रुपये की लागत वाली 5 बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इनमें चार रेलवे प्रोजेक्ट और एक हाईवे प्रोजेक्ट शामिल हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि तीन रेलवे परियोजनाएं हावड़ा-चेन्नई हाई डेंसिटी नेटवर्क का हिस्सा हैं। इन परियोजनाओं के पूरा होने के बाद हावड़ा से चेन्नई तक लगातार चार रेलवे लाइन का कॉरिडोर तैयार करने में मदद मिलेगी। इससे ज्यादा ट्रेनें चलाना आसान होगा और माल ढुलाई की क्षमता भी बढ़ेगी। हावड़ा-चेन्नई रेल मार्ग देश के सबसे महत्वपूर्ण रेलवे कॉरिडोर में से एक है। इस रूट से पूर्वी भारत और दक्षिण भारत के बीच बड़ी संख्या में यात्री और मालगाड़ियां चलती हैं। कैबिनेट ने इस रूट पर तीन प्रमुख परियोजनाओं को मंजूरी दी है।

यात्री और माल परिवहन की क्षमता बढ़ेगी

केंद्र सरकार के मुताबिक, इन पांचों परियोजनाओं से यात्री और माल परिवहन की क्षमता बढ़ेगी। रेलवे और हाईवे की बेहतर कनेक्टिविटी से बंदरगाहों, औद्योगिक क्षेत्रों, खनन क्षेत्रों और प्रमुख शहरों के बीच सामान पहुंचाना आसान होगा। रेल परियोजनाओं से कुल मिलाकर बड़ी मात्रा में अतिरिक्त माल ढुलाई क्षमता तैयार होगी। इससे लॉजिस्टिक्स लागत घटाने, रोजगार पैदा करने और सड़क की तुलना में रेल के जरिए माल ढुलाई बढ़ाने में मदद मिलेगी।

बिहार में नेपाल सीमा तक बनेगा 4-लेन हाईवे

कैबिनेट ने बिहार के मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनबरसा (नेपाल सीमा) तक 83 किमी लंबे 4-लेन हाईवे के निर्माण को मंजूरी दी है। इसकी लागत 3,591 करोड़ रुपये है। इसे हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के तहत विकसित किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट को 30 महीने में पूरा करने का लक्ष्य है। इसमें सात बड़े पुल, तीन रोड ओवर ब्रिज, छह व्हीकुलर अंडरपास और बागमती नदी पर 340 मीटर लंबा बड़ा पुल शामिल होगा। इसके तैयार होने से मुजफ्फरपुर से नेपाल सीमा तक का सफर 2 घंटे से घटकर सिर्फ 1 घंटा रह जाएगा। साथ ही माता जानकी मंदिर (पुनौरा धाम) और बाबा गरीबनाथ मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं को आसानी होगी।

बहनों को 39वीं किस्त और रक्षा बंधन का शगुन मिला

'फूलों का तारों का...' गाते-गाते सीएम ने लाड़ली बहनों पर लुटाया प्यार

मैहर (नप्र)। प्रदेश की सवा करोड़ से अधिक लाड़ली बहनों को प्रदेश की मोहन सरकार ने रक्षाबंधन के पहले ही 250 रुपए का गिफ्ट दिया है। सीएम मोहन यादव ने मैहर में लाड़ली बहनों के लिए मंच से, फूलों का तारों का सबका कहना है, एक हजारों में मेरी बहना है...गाना गाते हुए 1750 रुपए खातों में ट्रांसफर किए। इस मौके पर उन्होंने बहनों से राखी भी बंधवाई। मैहर जिले को भी करोड़ों के विकास कार्यों की सौगातें मिली हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मैहर में समारोहपूर्वक मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना की राशि सिंगल क्लिक से हितग्राही बहनों के बैंक खातों में अंतरित की और विभिन्न विकास कार्यों के भूमि पूजन व लोकार्पण समारोह में आयोजित प्रदर्शनी का अवलोकन किया। लोकार्पण समारोह में बहनों को झूला झुलाया।

मुख्यमंत्री मोहन यादव बुधवार को मैहर में आयोजित कार्यक्रम में लाड़ली बहनों के बीच अलग ही अंदाज में नजर आए। राखी से पहले आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने मंच से 'फूलों का तारों का सबका कहना है...' गीत गाकर बहनों के प्रति अपना स्नेह जताया। इसके बाद उन्होंने प्रदेश की 1.25 करोड़ से अधिक लाड़ली बहनों के बैंक खातों में 2148 करोड़ की राशि ट्रांसफर की। इसमें नियमित 1500 के साथ सावन के अवसर पर 250 का अतिरिक्त शगुन शामिल है। इस तरह पात्र बहनों को इस बार कुल 1750 की राशि मिली। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में लाड़ली बहनों पर पुष्प वर्षा की और विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को हितलाभ वितरित किए। जनअभियान परिषद की सखियों ने मुख्यमंत्री को विशाल राखी भी भेंट की।

राखी साल में एक बार, हम हर महीने मनाते हैं उत्सव- मुख्यमंत्री ने कहा कि राखी का त्योहार साल में एक बार आता है, लेकिन उनकी सरकार हर महीने लाड़ली बहनों को राशि देकर इस उत्सव को मनाती है। उन्होंने कहा कि बहनों का प्रेम और आशीर्वाद सरकार के लिए सबसे बड़ी ताकत है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने चुनाव के समय जो वादा किया था, उसे लगातार पूरा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आने वाले पांच साल तक लाड़ली बहनों को राशि देने का फैसला किया गया है। उन्होंने बहनों से अपील की कि खाते में राशि आने के बाद अपने भाइयों को मिठाई खिलाएं और टीका करें। उन्होंने कहा कि वे इसे अपना आशीर्वाद मानेंगे।

कई घरों के लिए लाड़ली बहना योजना की राशि बहुत महत्व रखती है

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि हम सभी जानते हैं कि कई घरों के लिए लाड़ली बहना योजना की राशि बहुत महत्व रखती है। इस राशि से कई घरों में सकारात्मकता और सुविधा का संचार हुआ है। कई बहनों ने निरंतर प्राप्त हो रही इस राशि के आधार पर अपने स्तर पर आय के स्रोत विकसित किए है। कई बहनें सिलाई मशीन या गोपालन के माध्यम से घर की आय में योगदान दे रही हैं। लाड़ली बहना योजना से कई घरों का आर्थिक तंत्र बदला है। यह इस बात का संकेत है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि माता-पिता के परिवार से विदा होकर दूसरे परिवार में जाना, बहनों के जीवन का एक चुनौती पूर्ण पक्ष है। नए परिवार में अपना स्थान बनाना, स्नेह और अपने सामर्थ्य से नए परिवार की धुरी बनना, बहनों की हिम्मत को दर्शाता है। ऐसी स्थिति में बहनों की थोड़ी मदद उनके सम्मान और आत्मविश्वास के लिए जरूरी है। राज्य सरकार बहनों के जीवन में सुख समृद्धि लाने और उनके सपनों को साकार करने में मदद के लिए ही लाडली बहना योजना संचालित कर रही है। बहनों की छोटी-छोटी ज़रूरतें उनकी राह में कभी रुकावट ना बने, वे आत्मनिर्भर बनें हमारा यही प्रयास है।

- पार्सल की भी सुविधा, असम और हिमाचल में ड्रोन सेवा की शुरुआत

अब डाकिए का इंतजार खत्म! आसमान से पहुंचेगी चिट्ठी

नई दिल्ली (एजेंसी)। दूर-दराज के गांवों तक डाक पहुंचाने का तरीका बदलने जा रहा है। पहाड़ों और मुश्किल रास्तों के बीच अब डाक का इंतजार कम होगा। इंडिया पोस्ट ने दुर्गम इलाकों में डाक के बैग पहुंचाने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल शुरू किया है। हिमाचल प्रदेश में 12 जून से मंडी-रेहड़धार मार्ग पर इसकी शुरुआत हुई और अब असम में भी पहली ड्रोन उड़ान के साथ इस व्यवस्था का विस्तार किया गया है। विभाग का लक्ष्य असम और हिमाचल प्रदेश में करीब 150 निर्धारित मार्गों पर ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करना है।

असम में पहली बार ड्रोन से पहुंची डाक

असम में इस सप्ताह पहली बार डाक के बैग पहुंचाने के लिए ड्रोन उड़ाया गया। यह पहल उन इलाकों को ध्यान में रखकर की गई है, जहां खराब सड़क, लंबी दूरी, बाढ़ या कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के कारण सड़क मार्ग से डाक पहुंचाने में ज्यादा समय लगता है। प्रस्तावित नेटवर्क में अकेले असम के करीब 40 मार्ग शामिल हैं। इसका मकसद दूर-दराज के क्षेत्रों में डाक सेवा को तेज और अधिक भरोसेमंद बनाना है।

स्काईएयर मोबिलिटी के साथ साझेदारी

इंडिया पोस्ट ने इस पहल के लिए गुरुग्राम की ड्रोन वितरण और तकनीकी कंपनी स्काई एयर मोबिलिटी के साथ साझेदारी की है। इसके तहत ड्रोन खाता डाकघरों से शाखा डाकघरों के बीच डाक के बैग पहुंचाएंगे। कंपनी के मुताबिक प्रस्तावित नेटवर्क हिमाचल प्रदेश और असम में करीब 150 मार्गों को जोड़ेगा।

बच्चों को संपत्ति से बेदखल कर सकते हैं माता-पिता

नई दिल्ली (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि सीनियर सिटीजन्स अपने बच्चों को संपत्ति से बेदखल कर सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि बढ़ती उम्र का मतलब असुरक्षा या

- सुप्रीम कोर्ट का आदेश, कहा-असुरक्षा या अपमान नहीं होना चाहिए

अपमान नहीं होना चाहिए। हर व्यक्ति को जीवनभर गरिमा के साथ जीने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश को भी पलट दिया, जिसमें बेटे और बहू को मकान से बेदखल करने के ट्रिब्यूनल कोर्ट के आदेश को रद्द किया गया था। कोर्ट ने कहा कि बुजुर्गों की गरिमा के लिए ट्रिब्यूनल के पास बच्चों को संपत्ति से निकालने का आदेश देने का अधिकार है। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की बेंच ने कहा कि कानून का मकसद बुजुर्गों की गरिमा और सुरक्षा तय करना है। सभ्य समाज का स्तर अक्सर इस बात से तय होता है कि वह अपने बुजुर्गों को कितनी गरिमा, सम्मान और सुरक्षा देता है।

भोपाल का तापमान
अधिकतम 20 °c
न्यूनतम 18°c

सुबह सवेरे

इंदौर ■ गुरुवार, 20 अगस्त 2026

जो अग्नि हमें गर्मी देती है , हमें नष्ट भी कर सकती है ; यह अग्नि का दोष नहीं है।
चाणक्य नीति

सरकार को 3 ऑप्शन...वर्ना भोपाल बंद की चेतावनी

दुकानदार बोले–क्या भीख मांगकर बच्चों का पेट भरेंगे ; इधर, 7158 नोटिस जारी

भोपाल (नप्र)। 'सरकार को 3 ऑप्शन देते हैं। पहला- मास्टर प्लान लागू करें, दूसरा- गुजरात की तर्ज पर मिक्स लैंड यूज लागू करें और तीसरा- निगम की सीलिंग की कार्रवाई रोके। यदि ऐसा नहीं किया तो भोपाल को अनिश्चितकाल के लिए बंद कर देंगे। सड़कें जाम करेंगे और सीएम हाउस का घेराव करेंगे।'

यह चेतावनी भोपाल व्यापारियों ने सरकार को दी है। 10 नंबर मार्केट व्यापारी महासंघ के अध्यक्ष आनंद सोनी ने कहा कि हमें चैन की नींद सोने दिया जाए। उनके पेट पर लात नहीं मारें।

रहवासी इलाकों में कमर्शियल एक्टिविटी पर नगर निगम के नोटिस और सीलिंग की कार्रवाई शुरू करने के बाद भोपाल के व्यापारी भी सड़क पर उतर गए हैं। मंगलवार को उन्होंने रोशनपुरा चौराहे पर बड़ा प्रदर्शन किया।

अध्यक्ष सोनी ने बताया कि सरकार लाखों लोगों को बेरोजगार कर रही हैं। वर्ष 2005 से पेंडिंग मास्टर प्लान यदि पहले ही लागू हो जाता तो आज यह हालात नहीं बनते। भोपाल में व्यापारियों पर कार्रवाई हुई तो 90% व्यापार ही बंद हो जाएगा। जिसका सीधा असर आम जनता पर पड़ेगा।

बच्चों की फीस कैसे भरेंगे? बेरोजगार हो जाएंगे– हाउसिंग बोर्ड के कारोबारी राहुल जैन ने बताया कि निगम के नोटिस आ रहे। इससे चिंता बढ़ गई हैं। दुकानदार पहले ही कर्जे में है। सरकार ने ही बिजली के कमर्शियल मीटर लगाए, दुकान की रजिस्ट्री की, नगर निगम को सारे टैक्स दे रहे तो फिर यह कार्रवाई क्यों? ऐसा हुआ तो बच्चों की स्कूल फीस कैसे भरेंगे? हम तो बेरोजगार हो जाएंगे।

मास्टर प्लान नहीं आना सरकार की विफलता– सीनियर एडवोकेट एहतेशाम कुरैशी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने रहवासी इलाकों में कमर्शियल एक्टिविटी को लेकर आदेश दिया है। साल 2024 और 2025 में जजमेंट आया था। इसके बाद तमिलनाडु में याचिका लगी, जिसमें मध्य प्रदेश भी पार्टी है। याचिका में नगर निगम ने तथ्यों के साथ बताया है। शपथ पत्र में ही कहा है कि 2005 से मास्टर प्लान नहीं आया है।

कुरैशी का कहना है कि भोपाल में मास्टर प्लान सरकार को लाना है। चीफ सेक्रेटरी को हाईकोर्ट में पक्ष रखना था। मुख्यमंत्री को सलाह देना थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यदि सरकार अपनी पक्ष मजबूती से रखती तो आज ये हालात नहीं बनते। राज्य सरकार चाहे तो वर्तमान की गतिविधियों को नियमित कर सकती है।

3 दिन की मोहलत, फिर सीलिंग की कार्रवाई

भोपाल में आवासीय भवनों के कमर्शियल उपयोग पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद नगर निगम ने नोटिस दे रहा है। मंगलवार को भी नोटिस दिए गए। अब तक साढ़े 7 हजार से ज्यादा नोटिस जारी किए जा चुके हैं। इनमें नरेला और गोविंदपुरा विधानसभाओं में नोटिस की संख्या सबसे ज्यादा है। नगर निगम के मुताबिक, कुल नोटिस में से 3 दिन में अधिभोग उल्लंघन की अवधि समाप्त होने वाले करीब एक हजार नोटिस शामिल हैं। उपायुक्त भुवन गुप्ता ने बताया कि अब निगम आगे की कार्रवाई करेगी। जिसमें अधिभोग उल्लंघन के मामलों में गुण–दोष पर परिक्षण करते हुए अंतिम आदेश पारित किया जाएगा।

संक्षिप्त समाचार

झारखंड में प्रदर्शनकारी छात्रों का आंदोलन हो गया खत्म

- सरकार के निर्णय के बाद प्रदर्शनकारियों ने लिया फैसला

रांची (एजेंसी)। जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितता के खिलाफ रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्रों का आंदोलन समाप्त हो गया। बुधवार को जेपीएससी-

जेएसएससी अभ्यर्थी न्याय मंच ने आंदोलन समाप्त करने का ऐलान किया। हालांकि दूसरे गुट के छात्र आगे की रणनीति पर बैठक कर रहे हैं और जल्द ही उनकी ओर से भी आंदोलन को समाप्त किए जाने की घोषणा किए जाने का संकेत दिया गया है। जेपीएससी-जेएसएससी अभ्यर्थी न्याय मंचके छात्र नेता रामावतार महतो ने फिलहाल अपने प्रदर्शन को समाप्त करने की।

हॉकी वर्ल्डकप
भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराया

एम्सटेलवीन (एजेंसी)। भारत ने मेंस हॉकी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को 0-0 से हरा दिया है। इसी के साथ टीम टूर्नामेंट के टॉप-8 राउंड में प्रवेश कर गई है। वहीं, पाकिस्तान बाहर हो गया है। एम्सटेलवीन के वेगनर हॉकी स्टेडियम में भारतीय कप्तान हरमनप्रीत सिंह, अभिषेक ने 2-2 गोल किए। जबकि, हार्दिक सिंह और सुखजीत सिंह ने एक-एक गोल दागे। पाकिस्तान की ओर से हन्नान शाहीद ने गोल गोल किए। एक गोल सुफियान खान की स्टिक से आया।

दिल्ली के टिकरी कलां में सीएनजी पंप पर गैस भरवा रहे ट्रक में धमाका, 3 की मौत, कई घायल

नई दिल्ली (एजेंसी)। आउटर दिल्ली के मुंडका इलाके के टिकरी कलां में बुधवार को एक सीएनजी पंप पर बड़ा हादसा हो गया। टिकरी कलां मेट्रो स्टेशन के पास स्थित सीएनजी पंप पर एक ट्रक का सीएनजी सिलेंडर फटने से जोरदार धमाका हुआ। धमाके के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। पुलिस के मुताबिक, हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई है, जबकि तीन अन्य लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं। पुलिस के मुताबिक, मनीष की मौके पर ही मौत हो गई।

कोलकाता की पांच मंजिला बिल्डिंग में भीषण आग

- 9 लोगों की मौत, इनमें कुछ बांग्लादेशी नागरिक शामिल

कोलकाता (एजेंसी)। कोलकाता के मिर्जा गालिब स्ट्रीट स्थित पांच मंजिला बिल्डिंग में मंगलवार रात करीब 1.45 बजे आग लग गई। बिल्डिंग के अंदर कई होटल थे। हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई, इनमें 2 महिलाएं और एक 4 साल का बच्चा शामिल है। सभी बेहोशी की हालत में मिले थे। 6 लोग घायल हुए हैं। अब तक 80 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। आग लगने के वक्त होटलों में ज्यादातर लोग सो रहे थे। बिल्डिंग में धुआं भरने के कारण उनका दम घुटने लगा।

सप्रे संग्रहालय की प्रचुर संदर्भ संपदा देख कर यू.के. हिंदी समिति अभिभूत

भोपाल / युनाइटेड किंगडम (ब्रिटेन) में हिन्दी के प्रचार-प्रसार में संलग्न यू.के. हिन्दी समिति के समूह ने 19 अगस्त को माधवराव सप्रे स्मृति समाचारपत्र संग्रहालय का अवलोकन किया। समिति की अध्यक्ष सुश्री सुरेखा चोफला सप्रे संग्रहालय में संग्रहीत प्रचुर संदर्भ संपदा देखकर अभिभूत हो गईं। उनकी प्रतिक्रिया रही- यह संस्थान जिज्ञासुओं की ज्ञानपिपासा का समाधान करने में असाधारण भूमिका निभा रहा है। सुरेखा जी की अगुआई में यू.के. के प्रतिभाशाली हिन्दी विद्यार्थियों का समूह भारत आया हुआ है। समूह ने सर्वप्रथम दुर्लभ संदर्भ सामग्री का अवलोकन किया। पश्चात हिन्दी पत्रकारिता के दो सौ साल के इतिहास के प्रमुख पत्र-पत्रिकाओं की प्रदर्शनी (पी.पी.टी.) देखी। संस्थापक विजयदत्त श्रीधर से सवाल-जवाब किए। सप्रे संग्रहालय की ओर से प्रबंधक विवेक श्रीधर ने हिन्दी पत्रकारिता द्विशताब्दी के उपलक्ष्य में भारत सरकार द्वारा जारी विशेष डाक टिकट का एल्बम सुरेखा जी को भेंट किया। रवीन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय के डा. अरुण पाण्डेय, शोध निदेशक डा. मंगला अनुजा, प्रशासनिक अधिकारी साधना देवांगन, लाइब्रेरियन गोल्डी पाण्डेय ने समूह का मार्गदर्शन किया।

ओटी टेक्नीशियन भर्ती पर हाईकोर्ट की रोक

288 पदों पर भर्ती में पात्रता नियम बदलने का मामला ; हाईकोर्ट ने शासन–कर्मचारी चयन मंडल से मांगा जवाब

जबलपुर (नप्र)। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत ओटी टेक्नीशियन के 288 पदों पर चल रही भर्ती प्रक्रिया में अंतरिम आदेश जारी करते हुए 31 मार्च 2026 को जारी मेरिट लिस्ट और उसके आधार पर की गई नियुक्तियों पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने राज्य शासन, संबंधित विभागों और कर्मचारी चयन मंडल सहित अन्य पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

मामला भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद ओटी टेक्नीशियन पद की पात्रता शर्तों में किए गए बदलाव से जुड़ा है। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता आर्यन उर्मलिया ने कोर्ट में दलील दी कि भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद पात्रता के मूल नियमों में बदलाव कर नए अभ्यर्थियों को लाभ देना संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 में मिले समान अवसर के अधिकार के खिलाफ है।

भर्ती के बाद बदले पात्रता नियम– याचिकाकर्ताओं के मुताबिक भर्ती का विज्ञापन जारी होने के समय ओटी टेक्नीशियन पद के लिए जो शैक्षणिक योग्यता और प्रमाण-पत्र संबंधी शर्तें तय थीं, अभ्यर्थियों ने उन्हीं के आधार पर आवेदन किया और चयन प्रक्रिया में शामिल हुए। इसके बाद शासन ने 10 अगस्त 2026 को राजपत्र अधिसूचना जारी कर पात्रता संबंधी प्रावधान में बदलाव कर दिया।

याचिकाकर्ताओं का कहना है कि भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद ऐसा संशोधन नहीं किया जा सकता, जिससे वे अभ्यर्थी भी पात्र हो जाएं जो विज्ञापन जारी होने के समय निर्धारित योग्यता पूरी नहीं करते थे। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न फैसलों का हवाला भी दिया गया। याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट में स्पष्ट किया कि निजी संस्थानों से प्राप्त योग्यता को भविष्य की भर्तियों में मान्यता दिए जाने पर उन्हें आपत्ति नहीं है। उनकी आपत्ति केवल यह है कि बाद में किए गए संशोधन को मौजूदा भर्ती प्रक्रिया पर लागू किया जा रहा है। इससे मूल विज्ञापन की शर्तों के आधार पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के अधिकार प्रभावित हो सकते हैं। अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि भर्ती की मेरिट लिस्ट 31 मार्च 2026 को जारी हो चुकी थी, जबकि पात्रता संबंधी संशोधन 10 अगस्त 2026 को किया गया। संशोधित प्रावधानों के आधार पर कुछ अभ्यर्थियों को नियुक्ति भी दी जा चुकी है।

मेरिट लिस्ट और नियुक्तियों पर अंतरिम रोक

मामले की सुनवाई जस्टिस विवेक कुमार सिंह की एकलपीठ में हुई। कोर्ट ने प्रथमदृष्टया मामले को विचारणीय मानते हुए 31 मार्च 2026 को जारी मेरिट लिस्ट और उसके आधार पर की गई नियुक्तियों पर अंतरिम रोक लगा दी। राज्य शासन, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, कर्मचारी चयन मंडल सहित संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किए गए हैं। कोर्ट के आदेश के बाद फिलहाल इस मेरिट लिस्ट के आधार पर आगे की नियुक्तियों पर भी रोक रहेगी। मामले की अगली सुनवाई 5 सितंबर 2026 को होगी। याचिकाकर्ताओं ने मांग की है कि 10 अगस्त 2026 के संशोधन को वर्तमान भर्ती पर लागू न किया जाए और मूल विज्ञापन में तय पात्रता शर्तों के आधार पर भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाते हुए संशोधित मेरिट लिस्ट तैयार की जाए।

बिहार में छात्रों के समर्थन में आरजेडी का प्रदर्शन

- तेजस्वी यादव हिरासत में लिए गए,वाटर कैनन चलाई गई

पटना (एजेंसी)। बिहार के सीवान में छात्र आंदोलन के दौरान एके-47 से फायरिंग के मामले को लेकर तेजस्वी यादव बुधवार को सड़क पर उतरे। उन्होंने पटना में जेपी गोलंबर से राजभवन तक मार्च निकाला। करीब 5 किलोमीटर लंबे मार्च में उनके साथ करीब 5 हजार समर्थक मौजूद रहे। समर्थकों के साथ तेजस्वी डाकबंगले पर लगाई बैरिकेडिंग तोड़कर आगे निकल गए। इनकम टैक्स चौराहे पर पुलिस ने वाटर कैनन चलाई। इसके बाद तेजस्वी को हिरासत में ले लिया गया। उन्होंने कहा कि मैं जेल से डरने वाला नहीं हूं। हमारे भगवान श्री कृष्ण का जन्म जेल में ही हुआ था। जो सत्ता में आया है, उसका जाना तय है। कुछ कार्यकर्ताओं ने पुलिस के ऊपर पानी की बोतलें भी फेंकीं।

मीसा भारती ने कहा- डीएम को हटाए जाने तक हम डटे रहेंगे

प्रदर्शन के दौरान मीडिया से बातचीत में राजद की नेता मीसा भारती ने कहा कि राजद कार्यकर्ता और बिहार के छात्र जेल जाने के लिए भी तैयार हैं। उन्होंने कहा कि जब तक सीवान के डीएम को सस्पेंड नहीं किया जाता है, तब तक हम डटे रहेंगे। वाटर कैनन के इस्तेमाल के सवाल पर उन्होंने कहा कि ये तो बहुत छोटी बात है, अगले कुछ दिनों में सरकार बंदूकों का इस्तेमाल करती भी दिखाई दे सकती है।

नीट का सिस्टम फुलप्रूफ इसे तोड़ना बड़ा मुश्किल

- सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने कहा-पूरी प्रक्रिया बेहद गोपनीय रखी जाती है

नई दिल्ली (एजेंसी)। सरकार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा कि नीट परीक्षा सिस्टम पूरी तरह सुरक्षित है। इसमें सेंध लगाना मुश्किल है। पेपर तैयार करने से लेकर एग्जाम सेंटर में पहुंचने तक पूरी प्रक्रिया को बेहद गोपनीयता रखा जाता है। वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) से यूपीएससी जैसा मजबूत परीक्षा सिस्टम बनाने को कहा। कोर्ट ने कहा कि नई टेक्नोलॉजी समझने वाले अधिकारियों को शामिल करना चाहिए। साथ ही अनुभवी अधिकारियों के बार-बार ट्रांसफर से बचने की सलाह दी। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की बेंच ने यूनाइटेड डॉक्टर्स फ्रंट और अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई की।

मैं इस लड़ाई में आदिवासी भाई-बहनों के साथःराहुल

केन-बेतवा लिंक प्रोजेक्ट के प्रभावितों से मिले कांग्रेस नेता

छतरपुर (एजेंसी)। छतरपुर में केन-बेतवा लिंक प्रोजेक्ट के खिलाफ चल रहे आंदोलन के प्रमुख कार्यकर्ता अमित भटनागर ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने प्रोजेक्ट से प्रभावित आदिवासी परिवारों की समस्याओं, विस्थापन, पुनर्वास और अधिकारों से जुड़े मुद्दों को राहुल गांधी के सामने रखा। आंदोलन कारियों ने राहुल को बताया कि प्रभावित आदिवासी समुदाय लंबे समय से अपने अधिकारों और न्याय की मांग को लेकर सत्याग्रह कर रहा है।

विस्थापन और पुनर्वास का मुद्दा

आंदोलन कारियों ने राहुल गांधी को बताया कि केन–बेतवा प्रोजेक्ट से पन्ना और छतरपुर जिले के बड़ी संख्या में परिवार प्रभावित हो रहे हैं। उनका कहना है कि प्रोजेक्ट के चलते आदिवासी समुदाय को विस्थापन और आजीविका से जुड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रभावित परिवारों ने भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और अपने अधिकारों से जुड़े मुद्दे भी उठाए।

जेन जी को साधने में लगा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ

तीन दिन की समन्वय बैठक में तय किया जाएगा रोडमैप

नई दिल्ली (एजेंसी)। जंतर-मंतर के साथ ही रांची में हुए छात्र आंदोलन से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भी जोर युवाओं की ओर बढ़ा है। इसलिए 19 से 21 अगस्त के बीच

- युवाओं को केंद्र में रखकर रोजगार, शिक्षा पर चर्चा होगी
- नशा मुक्ति और जनसांख्यिकीय असंतुलन भी प्रमुख मुद्दे

विशाखापत्तनम में सरसंघचालक व सरकार्यवाह की मौजूदगी में भाजपा, एबीवीपी समेत 32 संगठनों के शीर्ष पदाधिकारियों की अखिल भारतीय समन्वय बैठक होने जा रही है। इस बैठक में युवाओं को केंद्र में रखते हुए एक रोडमैप तैयार किया जाएगा। प्रति वर्ष होने वाली इस समन्वय बैठक में सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत, सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले, सभी सह सरकार्यवाह और अन्य केंद्रीय अधिकारियों की विशेष मौजूदगी रहेगी। कुल 327 प्रतिनिधियों के आने की उम्मीद है। इस बैठक में युवा आंदोलनों के साथ शिक्षा व परीक्षा व्यवस्था को लेकर उनकी दिक्कतों व अपेक्षाओं के साथ उनके लिए बड़ा मुद्दा बन रहे रोजगार पर भी चर्चा होगी। स्वरोजगार प्रेरित करने पर भी जोर होगा। शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रमों को अब युवा लक्षित करने पर विशेष जोर है। संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर ने बताया कि युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं, आने वाले समय में सभी संगठन उस दिशा में क्या कर सकते हैं।

संघ के प्रति बढ़ा युवाओं का आकर्षण

संघ शताब्दी वर्ष में युवाओं का आरएसएस के प्रति आकर्षण बढ़ा है। संघ की वेबसाइट पर ज्वॉइन आरएसएस के माध्यम से वर्ष 2025 में जनवरी से जुलाई के बीच 55 हजार 423 लोगों ने संघ से जुड़ने के लिए पंजीकरण करवाया था। 2026 में इसी अवधि के बीच यह संख्या ढाई गुना बढ़कर एक लाख 23 हजार 287 हो गई है। जुलाई 2025 में इनकी संख्या 9718 रही, जबकि जुलाई 2026 में 24 हजार 86 लोगों ने पंजीकरण कराया है। इनमें 30 वर्ष से कम आयु के युवा करीब 65 प्रतिशत हैं।

मराठी नहीं जानने वाले महाराष्ट्र में ऑटो-टैक्सी नहीं चला पाएंगे

- ट्रांसपोर्ट मंत्री बोले-पहले नोटिस देंगे,3 महीने में नहीं सीखे तो लाइसेंस रद्द होगा

मुंबई (एजेंसी)। मराठी भाषा नहीं जानने वाले ड्राइवर अब महाराष्ट्र में ऑटो-टैक्सी नहीं चला पाएंगे। राज्य सरकार 20 अगस्त से उन ऑटो-रिक्शा और टैक्सी ड्राइवरों के खिलाफ अभियान शुरू करने वाली है, जिनके पास मराठी का 'वर्किंग नॉलेज' नहीं है। ट्रांसपोर्ट मंत्री प्रताप सरनाईक ने बुधवार को इसका ऐलान किया। उन्होंने कहा कि ड्राइवरों को पहले नोटिस देकर 3 महीने में मराठी सीखने का मौका दिया जाएगा। इसके बाद भी मराठी नहीं सीखने पर लाइसेंस और बैज सस्पेंड किया जाएगा। यह अभियान पूरे राज्य में एक महीने तक चलेगा। अतिरिक्त परिवहन आयुक्त रवि गायकवाड़ पूरे महाराष्ट्र में इस एक महीने के अभियान की निगरानी करेंगे। परिवहन की फ्लाइंग स्क्वॉड ऑटो और टैक्सी ड्राइवरों की जांच करेंगी और नए नियमों का पालन हो रहा है या नहीं, यह देखेंगी।

जिलाबदर बदमाश शहर में घूमता पकड़ाया

इंदौर। आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए जिला बदर किए गए कुख्यात बदमाश अजय उर्फ भोला पठोते को लसूड़िया पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी जिला बदर अवधि का उल्लंघन कर राहुल गांधी नगर चौराहे स्थित एक डेयरी पर पहुंचा था। सूचना मिलने पर पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर उसे पकड़ लिया। आरोपी की पहचान अजय उर्फ भोला पिता सुरेश पठोते (22), निवासी राहुल गांधी नगर, इंदौर के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार उसके खिलाफ लसुड़िया सहित शहर के अलग-अलग थानों में लूट, अवैध वसूली, अवैध हथियार रखने और मारपीट सहित कई गंभीर अपराध दर्ज हैं। आरोपी की आपराधिक गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए लसूड़िया पुलिस ने जिला बदर का प्रतिवेदन पुलिस आयुक्त को भेजा था। इसके बाद पुलिस आयुक्त ने उसे तीन माह के लिए इंदौर जिले की राजस्व सीमा से बाहर रहने का आदेश दिया था। इसके बावजूद वह बिना अनुमति क्षेत्र में घूमता मिला। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ राज्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रकरण दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। कार्रवाई में थाना प्रभारी राजकुमार यादव सहित पुलिस टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

10 पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया

इंदौर। पुलिस और आमजन के बीच बेहतर संवाद स्थापित करने के साथ पुलिस के उल्लेखनीय कार्यों को प्रभावी ढंग से लोगों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले 10 पुलिस अधिकारियों-कर्मचारियों को मंगलवार को सम्मानित किया गया। पुलिस आयुक्त संतोष कुमार सिंह ने पलासिया स्थित पुलिस आयुक्त कार्यालय में आयोजित साप्ताहिक सम्मान कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों को प्रशस्ति पत्र और नगद पुरस्कार प्रदान किए। पुलिस कमिश्नरेट में जनोन्मुखी पुलिसिंग को बढ़ावा देने के लिए यह साप्ताहिक सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य बेहतर कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों का मनोबल बढ़ाने के साथ अन्य कर्मचारियों को भी उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रेरित करना है। पुलिस आयुक्त ने सम्मानित कर्मचारियों के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि पुलिस और जनता के बीच भरोसा मजबूत करने के लिए संवाद बेहद जरूरी है। उन्होंने पुलिसकर्मियों से सकारात्मक सोच और पूरी प्रतिबद्धता के साथ जिम्मेदारियों का निर्वहन करने का आह्वान किया।

अवैध कॉलोनियों के संपत्ति कर खाते खुलेंगे

इंदौर। अवैध कॉलोनियों में रहने वाले लोगों की संपत्तियों को लेकर नगर निगम ने बड़ा फैसला लिया है। महापौर पुष्यमित्र भार्गव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई महापौर परिषद की मैराथन बैठक में पूर्ण स्वामित्व के दस्तावेज उपलब्ध होने पर अवैध कॉलोनियों की निजी संपत्तियों और भूखंडों के संपत्ति कर खाते खोलने की मंजूरी दी गई। हालांकि शासकीय भूमि या अतिक्रमण वाली संपत्तियों पर संपत्ति कर जमा नहीं किया जाएगा। संपत्तियों के नामांतरण की प्रक्रिया सरल करने के लिए मानक प्रक्रिया तैयार करने का निर्णय भी लिया गया। बैठक में शहर के विकास को निजी भागीदारी और सामाजिक दायित्व के माध्यम से गति देने पर जोर रहा। रणजीत हनुमान मार्ग स्थित प्रस्तावित अंतरराष्ट्रीय तैराकी केंद्र के निर्माण के बाद संचालन और रखरखाव को निजी भागीदारी मॉडल पर देने का निर्णय लिया गया। फूटी कोठी पुल के नीचे खाली जमीन पर स्मार्ट केंद्र विकसित करने की मंजूरी भी मिली। शहर में आवागमन आसान करने के लिए कनाडिया रोड से खजराना मंदिर तक संपर्क सड़क बनाने को मंजूरी दी गई। सुभाष नगर और वल्लभ नगर में नए बाजार विकसित करने की दिशा में भी निगम कार्रवाई करेगा।

13 दिन में पकड़ाए नकबजन, माल बरामद

इंदौर। राऊ पुलिस ने पलाश परिसर स्थित फ्लैट में हुई नकबजनी का 13 दिन में खुलासा करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से सोने-चांदी के आभूषण और नकदी सहित करीब 3.20 लाख रुपए का मशरूका बरामद किया गया है। पुलिस अब उनसे शहर में हुई अन्य चोरी की वारदातों के बारे में पूछताछ कर रही है। 4 अगस्त को फ्लैट से सोने-चांदी के जेवर और नकदी चोरी होने की शिकायत पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया था। आरोपियों की तलाश में पुलिस ने घटनास्थल से लेकर उनके भागने के संभावित रास्तों तक लगे 100 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिर की सूचना से आरोपियों की पहचान हुई। 17 अगस्त को पुलिस ने खंडवा जिले के जलवा बुजुर्ग से रंजीत पिता लखन पवार (33) को गिरफ्तार किया। उसका साथी धर्मेंद्र पिता रामचंद्र पांचाल (44) इंदौर से पकड़ा गया। इनके कब्जे से सोने का नेकलेस, अन्य जेवर और नकदी बरामद हुई।

स्मार्ट सिटी की धंसी सड़क की जांच होगी

इंदौर। गोराकुंड चौराहे के पास करीब 40 करोड़ रुपए की लागत से बनी स्मार्ट सिटी सड़क का बड़ा हिस्सा अचानक धंस गया। सड़क के नीचे बिछाई गई नर्मदा लाइन की टेस्टिंग के दौरान रिसाव होने से पानी का तेज बहाव शुरू हुआ। दबाव बढ़ने के साथ ही सड़क की सतह बैठ गई और देखते ही देखते यहां बड़ा गड्ढा बन गया। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद स्मार्ट सिटी के कामों की गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो गए हैं। बताया जा रहा है कि सड़क का निर्माण करीब एक साल पहले हुआ था। करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद नई सड़क के इस तरह धंसने से निर्माण कार्य की गुणवत्ता और सड़क के नीचे किए गए भराव पर सवाल उठ रहे हैं। एमआईसी सदस्य बबलू शर्मा ने कहा कि यह काम वर्ष 2021 के स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत हुआ था। वर्ष 2022 में पुष्यमित्र भार्गव के नेतृत्व में परिषद बनने के बाद स्मार्ट सिटी के कार्यों को लेकर आपत्तियां दर्ज कराई गई थीं। महापौर की ओर से भी संबंधित कार्यों को लेकर पत्र लिखा गया था। उन्होंने बताया कि जिस कंपनी ने काम किया था, उसे ब्लैकलिस्ट किया गया था। अधूरी नर्मदा लाइन के कारण लोगों को परेशानी हो रही थी, इसलिए कुछ दिन पहले दूसरी एजेंसी से काम शुरू कराया गया था। लाइन की टेस्टिंग के दौरान रिसाव हुआ और तेज बहाव के कारण सड़क धंस गई। शर्मा ने कहा कि पूरे मामले की जांच कराई जाएगी और जांच में जो भी जिम्मेदार पाया जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी।

अमिता पुरोहित की मौत का मामला गरमाया

इंदौर। सुदर्शन बाग निवासी अमिता पुरोहित की संदिग्ध मौत का मामला अब गंभीर आरोपों के बीच तूल पकड़ता जा रहा है। मृतका के परिजनों ने पति और ससुराल पक्ष पर जहर देकर हत्या करने तथा घटना के बाद महत्वपूर्ण साक्ष्य छिपाने का आरोप लगाया है। मृतका के भाई संतोष पाठक ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित करने की मांग पुलिस प्रशासन से की है। परिजनों का आरोप है कि घटना की जानकारी कई घंटे तक मायके पक्ष और स्थानीय रिश्तेदारों को नहीं दी गई। उनका दावा है कि इस दौरान घटनास्थल से जुड़े साक्ष्यों को प्रभावित करने का प्रयास किया गया। परिजनों ने अस्पताल में दर्ज कराए गए मृत्यु पूर्व कथन को लेकर भी सवाल उठाए हैं। परिजनों के अनुसार अमिता पुरोहित जवाहर मार्ग स्थित 'नत्थी कलेक्शन' का संचालन करती थीं और सिलाई का काम भी करती थीं। उनका आरोप है कि संपत्ति और दुकान को लेकर ससुराल पक्ष के साथ विवाद चल रहा था। परिवार ने आरोपियों के मोबाइल फोन, बातचीत, संदेश, बैंक लेन-देन और स्थान संबंधी डिजिटल साक्ष्यों की जांच कराने की मांग की है।

बदहाल ट्रैफिक व्यवस्था पर हाईकोर्ट सख्त, कम ग्रीन सिग्नल पर भी सवाल

व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो गृह विभाग के प्रमुख सचिव को बुलाएंगे

इंदौर। शहर की बिगड़ी यातायात व्यवस्था को लेकर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने मंगलवार को कड़ा रुख अपनाया। यातायात नियमों के खुले उल्लंघन, ट्रैफिक पुलिस के अमले की कमी, बंद सीसीटीवी कैमरों, कम समय के ग्रीन सिग्नल, सड़कों के गड्ढों, जलभराव और कमजोर डिजिटल व्यवस्था पर कोर्ट ने चिंता जताई। कोर्ट ने संकेत दिया कि स्थिति में जल्द सुधार नहीं हुआ तो गृह विभाग के प्रमुख सचिव को व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में बुलाया जा सकता है। मामले की सुनवाई जस्टिस सुबोध अभ्यंकर और जस्टिस आलोक अवस्थी की डिवीजन बेंच ने वर्ष 2019 से लंबित जनहित याचिका पर की। याचिका राजलक्ष्मी फाउंडेशन की ओर से दायर की गई है। याचिकाकर्ता की ओर से सीनियर एडवोकेट अजय बागड़िया और एडवोकेट शिरीन सिलावट उपस्थित हुए। सुनवाई के दौरान जस्टिस सुबोध अभ्यंकर ने यातायात नियमों के उल्लंघन का अपना अनुभव भी बताया। उन्होंने कहा कि शहर में रेड लाइट तोड़ने की घटनाएं खुलेआम दिखाई देती हैं, लेकिन प्रभावी कार्रवाई नजर नहीं आती। उन्होंने बताया कि एक मोटरसाइकिल सवार रेड लाइट तोड़कर उनकी कार के पास तक आ गया था। कोर्ट ने इसे यातायात नियमों के पालन और उनके अमल की स्थिति पर गंभीर सवाल माना। सुनवाई में एडिशनल डीसीपी ट्रैफिक विक्रम सिंह रघुवंशी को विभाग की कमियों पर व्यक्तिगत रूप से स्पष्टीकरण देने के लिए बुलाया गया। कोर्ट ने स्वीकृत पदों, उपलब्ध पुलिस बल और रिक्त पदों सहित ट्रैफिक स्टाफ की वास्तविक स्थिति का विस्तृत ब्योरा भी मांगा।

पुलिस बल की संख्या कम

सुनवाई के दौरान बताया गया कि वर्ष 2013 में ही इंदौर की यातायात व्यवस्था के लिए 800 से अधिक अतिरिक्त कर्मियों की जरूरत बताई गई थी। इसके बावजूद स्वीकृत पदों का बड़ा हिस्सा अब भी खाली है। कोर्ट ने सवाल किया कि पर्याप्त पुलिस बल नहीं होने की स्थिति में यातायात नियमों का प्रभावी पालन कैसे कराया जा रहा है।

पुलिस बल की कमी के बीच यातायात निगरानी के लिए लगाए गए सीसीटीवी कैमरों की स्थिति पर भी कोर्ट ने सवाल उठाया। न्यायालय के सामने जानकारी आई कि शहर में लगे अधिकांश सीसीटीवी कैमरे फिलहाल बंद हैं। ऐसे में पुलिस बल और निगरानी व्यवस्था, दोनों की कमी के बीच नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई को लेकर सवाल खड़े हुए।

ग्रीन सिग्नल की अवधि कम

व्यस्त चौराहों पर ग्रीन सिग्नल की अवधि भी सुनवाई का मुद्दा बनी। कोर्ट को बताया गया कि कुछ चौराहों पर ग्रीन लाइट केवल 20 से 23 सेकंड तक रहती है। इतनी कम अवधि के कारण वाहनों की कतार और यातायात दबाव बढ़ने की स्थिति पर न्यायालय ने चिंता जताई। कोर्ट ने साफ किया कि इंदौर की मौजूदा यातायात व्यवस्था को लंबे समय तक इसी हालत में नहीं छोड़ा जा सकता। यदि जल्द सुधार नहीं हुआ तो गृह विभाग के प्रमुख सचिव को व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित होना पड़ सकता है।

इंदौर में पीओपी की प्रतिमाओं पर रोक, मिट्टी से निर्माण की अनुमति

पर्यावरण संरक्षण के निर्देश, रासायनिक रंगों पर भी पाबंदी

इंदौर। गणेश उत्सव और नवरात्रि से पहले इंदौर प्रशासन ने प्रतिमा निर्माण को लेकर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में सख्त कदम उठाया है। मूर्ति निर्माण से जुड़े पर्यावरणीय नियमों को लेकर मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय में मूर्तिकारों की बैठक आयोजित की गई। कलेक्टर शिवम वर्मा के निर्देशन में हुई बैठक की अध्यक्षता अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी रोशन राय ने की। बैठक में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों के साथ मूर्तिकार संघ के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निर्देशों के तहत जिले में अब भगवान श्री गणेश और माता दुर्गा की प्रतिमाओं के निर्माण में केवल पारंपरिक मिट्टी और प्राकृतिक सामग्री का इस्तेमाल किया जा सकेगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी पीओपी तथा अन्य रासायनिक पदार्थों से प्रतिमा बनाना प्रतिबंधित रहेगा।

अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी रोशन राय ने मूर्तिकारों को राष्ट्रीय हरित अधिकरण और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से जारी दिशा-निर्देशों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रतिमाओं के निर्माण में ऐसी सामग्री और प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए, जिससे पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि प्रतिमाओं के निर्माण में पारंपरिक मिट्टी का ही इस्तेमाल किया जाएगा। पकी हुई मिट्टी, पीओपी अथवा किसी भी प्रकार के रासायनिक पदार्थ से प्रतिमा तैयार करने की अनुमति नहीं होगी। पीओपी के स्थान पर कागज जैसी प्राकृतिक सामग्री का इस्तेमाल किया जा सकता है।

पर्यावरण संरक्षण का ध्यान रखें - अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया कि पहले से तैयार प्रतिमाओं के अलावा पीओपी या अन्य रासायनिक पदार्थों से नई प्रतिमाओं का निर्माण नहीं किया जा सकेगा। प्रशासन का जोर इस बात पर है कि त्योहारों के दौरान आस्था और परंपरा के साथ पर्यावरण संरक्षण का भी ध्यान रखा जाए। बैठक में मूर्तिकारों से प्रशासन के निर्देशों का पालन करने और प्रतिमा निर्माण की पुरानी प्राकृतिक परंपरा को अपनाने की अपील की गई। इससे प्रतिमाओं के विसर्जन के बाद जल, मिट्टी और आसपास के पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को कम करने में मदद मिलने की उम्मीद है।

गैर-विषाक्त रंग ही लगाएं

प्रतिमाओं को आकर्षक बनाने के लिए रंगों के इस्तेमाल को लेकर भी प्रशासन ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं। प्रतिमाओं पर केवल प्राकृतिक और गैर-विषाक्त रंग ही लगाए जा सकेंगे। रासायनिक अथवा विषैले रंगों के इस्तेमाल पर पूरी तरह रोक रहेगी। इसका उद्देश्य प्रतिमाओं के विसर्जन के बाद जल स्रोतों में होने वाले प्रदूषण को कम करना है। प्रशासन ने यह भी साफ कर दिया है कि जिले में केवल पारंपरिक मिट्टी से निर्मित प्रतिमाओं का ही उत्पादन और विक्रय किया जा सकेगा। पीओपी अथवा अन्य रासायनिक पदार्थों से बनी प्रतिमाओं का न तो जिले में उत्पादन किया जा सकेगा और न ही उनका विक्रय। ऐसी प्रतिमाओं को जिले से बाहर ले जाने या दूसरे स्थानों से जिले में लाने पर भी प्रतिबंध रहेगा।

पुलिस जांच में क्लीन चिट के बाद भाजपा पार्षद का निष्कासन खत्म

19 महीने बाद पार्टी में वापस, 6 साल के लिए निष्कासित हुए

इंदौर। भारतीय जनता पार्टी ने इंदौर के पार्षद जीतू यादव के खिलाफ की गई संगठनात्मक कार्रवाई को समाप्त कर दिया है। पुलिस जांच में क्लीन चिट मिलने के बाद पार्टी ने उनका निष्कासन वापस लेते हुए प्राथमिक सदस्यता बहाल कर दी है। जिला भाजपा अध्यक्ष सुमित मिश्रा की अनुशंसा पर प्रदेश संगठन ने यह फैसला लिया। इस संबंध में जिला अध्यक्ष को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक हेमंत खंडेलवाल के निर्देश पर 18 अगस्त 2026 को जीतू यादव का निष्कासन समाप्त कर दिया गया। जीतू यादव जनवरी 2025 में भाजपा पार्षद कमलेश कालरा के खातीवाला टैंक स्थित घर पर हुए हमले के बाद विवादों में आए थे। 3 और 4 जनवरी की दरमियानी रात कुछ बदमाश कालरा के घर पहुंचे थे। परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट और अभद्रता किए जाने का आरोप लगा था। इस घटना के बाद आरोप सामने आए थे कि हमलावर जीतू यादव के समर्थक थे और उनके इशारे पर यह घटना हुई।

मामले ने जल्द ही राजनीतिक रूप ले लिया था। कमलेश कालरा के परिवार के साथ हुई मारपीट और उनके नाबालिग बेटे के साथ कथित अभद्रता को लेकर भाजपा के भीतर भी विरोध हुआ था। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने भी घटना को गंभीरता से लिया था। बढ़ते विवाद के बीच जीतू यादव ने एमआईसी सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया था और पार्टी से भी अपना इस्तीफा सौंप दिया था। इसके बाद भाजपा प्रदेश नेतृत्व ने अनुशासनहीनता के मामले में जीतू यादव को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया था। पुलिस ने मामले में आरोपियों को गिरफ्तार किया था। पूरे घटनाक्रम की जांच के लिए विशेष जांच दल भी गठित किया गया था। संगठनात्मक कार्रवाई के बाद जीतू यादव लंबे समय तक भाजपा की प्राथमिक सदस्यता से बाहर रहे।

18 अगस्त को निष्कासन समाप्त- जिला संगठन की अनुशंसा पर प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के निर्देश से 18 अगस्त को निष्कासन समाप्त करने का आदेश जारी हुआ। इसके साथ ही जीतू यादव की भाजपा की प्राथमिक सदस्यता फिर से बहाल हो गई। हालांकि पार्टी संगठन में उन्हें फिलहाल कोई नई जिम्मेदारी दिए जाने की जानकारी सामने नहीं आई है। जनवरी 2025 में हुए विवाद के बाद संगठन की कार्रवाई का सामना कर रहे जीतू यादव की करीब 19 महीने बाद पार्टी में वापसी हुई है।

जनसुनवाई में अवैध निर्माण, संपत्ति कर घटाने के आवेदन सबसे ज्यादा

आवेदनों पर सुनवाई, संबंधित विभागों को कार्रवाई के निर्देश

इंदौर। नगर निगम की जनसुनवाई में मंगलवार को बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। इनमें सबसे ज्यादा आवेदन अवैध निर्माण, संपत्ति कर कम करने और राशन से जुड़ी राशि कम करने की मांग को लेकर सामने आए। निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल ने सभी आवेदनों पर सुनवाई कर उन्हें संबंधित विभागों को भेजने की जानकारी दी। जनसुनवाई के दौरान लोगों ने अपने-अपने क्षेत्रों में चल रहे निर्माण कार्यों और संपत्ति कर से जुड़ी आपत्तियां अधिकारियों के सामने रखीं। कई आवेदकों ने संपत्ति कर अधिक आने की शिकायत करते हुए उसे कम करने की मांग की। वहीं कुछ लोगों ने अवैध निर्माण से संबंधित शिकायत भी दर्ज कराईं। निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल ने बताया कि जनसुनवाई में प्राप्त सभी शिकायतों को संबंधित विभागों को सौंप दिया गया है। विभागीय अधिकारी शिकायतों की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। उन्होंने संपत्ति कर को लेकर कहा कि संपत्ति कर किसी संपत्ति का स्वामित्व प्रमाणित करने वाला दस्तावेज नहीं है। इसे नगर निगम द्वारा कर वसूली के लिए निर्धारित किया जाता है। कई बार शहर में ऐसे निर्माण भी हो जाते हैं, जिनकी जानकारी निगम के रिकॉर्ड में नहीं आ पाती और उन पर कर निर्धारित नहीं होता।

नौकरी का झांसा देकर ठगी, मूल दस्तावेज लौटाने के भी पैसे मांगते

आरोपी के पास से 313 युवाओं की मार्कशीट-डिग्रियां मिली

इंदौर। नौकरी दिलाने के नाम पर युवाओं से धोखाधड़ी करने और उनके मूल दस्तावेज वापस करने के बदले रुपए मांगने के मामले में विजयनगर पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने मुख्य आरोपी मयंक सर्राफ की पत्नी पूजा सर्राफ को भी गिरफ्तार किया है। इससे पहले पुलिस मयंक को गिरफ्तार कर उसके कार्यालय से 313 युवाओं की मूल मार्कशीट, डिग्रियां और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद कर चुकी है। पुलिस के मुताबिक मयंक सर्राफ अपनी कंसल्टेंसी के जरिए युवाओं को आकर्षक नौकरी दिलाने का झांसा देता था। नौकरी के लिए आवेदन के दौरान अभ्यर्थियों से उनकी मूल मार्कशीट,डिग्री और अन्य

दस्तावेज जमा करवा लिए जाते थे। जब नौकरी नहीं लगती और अभ्यर्थी अपने दस्तावेज वापस मांगते, तो उन्हें दस्तावेज लौटाने के बदले रुपए देने के लिए कहा जाता था। शिकायत मिलने के बाद विजयनगर पुलिस ने मयंक को गिरफ्तार किया था। जांच के दौरान उसके कार्यालय से बड़ी संख्या में मूल दस्तावेज मिलने के बाद पुलिस ने मामले की वित्तीय कड़ियां खंगालनी शुरू कीं। इसी दौरान पुलिस को पूजा सर्राफ के बैंक खाते में मामले से जुड़े संदिग्ध लेन-देन की जानकारी मिली। इसके आधार पर पुलिस ने उसे भी आरोपी बनाकर गिरफ्तार कर लिया।

अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त अमरेंद्र सिंह ने बताया कि दोनों आरोपियों के बैंक खातों और लेन-देन की जांच की जा रही है। साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि इस तरह कितने युवाओं को निशाना बनाया गया। पुलिस ने बरामद दस्तावेज उनके वास्तविक मालिकों तक पहुंचाने के लिए विशेष टीम गठित की है।

बाहर से आए घी पर खाद्य विभाग की कार्रवाई, 1750 लीटर जब्त

6.80 लाख के मंथन, श्री आनंद ब्रांड के घी के 18 नमूने लिए

इंदौर। दूसरे राज्यों से इंदौर पहुंच रहे घी की गुणवत्ता को लेकर खाद्य सुरक्षा प्रशासन ने जांच अभियान तेज कर दिया है। खाद्य सुरक्षा की टीम ने स्कीम नंबर 51 स्थित मां बगलामुखी इंटरप्राइजेज का निरीक्षण किया। यहां मंथन और श्री आनंद ब्रांड के घी की अलग-अलग पैकिंग और आकार में बड़ी मात्रा में भंडारण मिला। जांच के दौरान करीब 1750 लीटर घी जब्त किया गया, जिसकी अनुमानित कीमत 6.80 लाख रुपए बताई गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने प्रतिष्ठान में रखे घी की अलग-अलग पैकिंग और बैच से कुल 18 नमूने लिए हैं। इन नमूनों को खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता से जुड़े निर्धारित मानकों की जांच के लिए खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भेजा जा रहा है। प्रयोगशाला की रिपोर्ट आने तक मौके पर मौजूद करीब 1750 लीटर घी को जब्त रखा गया है। निरीक्षण के दौरान प्रतिष्ठान से मिली जानकारी के अनुसार मंथन और श्री आनंद ब्रांड का घी गुजरात में तैयार किया गया था और वहां से इंदौर लाया गया था।

बाहर के घी पर नजर - खाद्य सुरक्षा प्रशासन के अधिकारियों के अनुसार प्रदेश में बाहर से आने वाले घी और अन्य दुग्ध उत्पादों की गुणवत्ता पर विशेष नजर रखी जा रही है। निर्माताओं से लेकर डिपो, थोक विक्रेताओं और विक्रय केंद्रों तक नमूने लिए जा रहे हैं। इनकी जांच यह पता लगाने के लिए की जा रही है कि संबंधित खाद्य उत्पाद तय गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा मानकों पर खरे उतरते हैं या नहीं।

आगे की कार्रवाई तय

मां बगलामुखी एंटरप्राइजेज से लिए गए सभी 18 नमूनों की जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। यदि जांच में खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन सामने आता है तो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार संबंधित पक्ष के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। खाद्य सुरक्षा प्रशासन ने कहा है कि दूसरे राज्यों से इंदौर और मध्य प्रदेश में पहुंचने वाले घी समेत अन्य खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की निगरानी लगातार जारी रहेगी। अमानक, मिलावटी या असुरक्षित खाद्य पदार्थों के निर्माण, परिवहन, भंडारण और बिक्री के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रखी जाएगी।

संपादकीय

यह राजनीतिक सशक्तिकरण भी!

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा प्रदेश में जारी लाड़ली बहना और लाड़ली लक्ष्मी योजना को और पांच साल तक जारी रखने का फैसला महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही, साथ में महिलाओं के वोटों को आने वाले तीन चुनावों के लिए पक्का करने का राजनीतिक निर्णय भी है। भले ही इसके लिए सरकार के बजट पर भारी दबाव पड़ रहा हो और सरकारी तंत्र कर्ज के भरोसे चल रहा हो। मंगलवार को मोहन यादव कैबिनेट बैठक में इन दोनों योजनाओं को अगले 5 साल तक जारी रखने का फैसला लिया गया। इसके तहत सरकार लाड़ली बहना योजना पर 1 लाख 14 हजार 365 करोड़ और लाड़ली लक्ष्मी योजना पर 16 हजार 326 करोड़ रुपए खर्च करेगी। खास बात यह कि मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना में इस बार रक्षाबंधन पर लाभार्थियों को 250 रुपए अतिरिक्त दिए जाएंगे। हर महीने मिलने वाली 1500 रुपए की किस्त के साथ यह राशि जुड़ने से 19 अगस्त को लाड़ली बहनों के खातों में कुल 1750 रुपए पहुंचाए। लाड़ली बहना की 39वीं किश्त मुख्यमंत्री ने बुधवार को मैहर में आयोजित कार्यक्रम में ट्रांसफर भी कर दी। मुख्यमंत्री ने सिंगल क्लिक के जरिए प्रदेश की 1 करोड़ 25 लाख 13 हजार से अधिक पात्र महिलाओं के बैंक खातों में कुल 2,148 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि अंतरित की। इसी तरह राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। इसमें 60% केंद्र जबकि 40% राज्य का हिस्सा रहेगा। इसके अलावा उज्ज्वला योजना का लाभ लेने वाली पात्र महिलाओं को भी इस बार 250 रुपए की अतिरिक्त राशि दी जाएगी। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना की शुरुआत पूर्व मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान के कार्यकाल में जून 2023 में हुई थी। अगस्त 2026 तक योजना की 39 किस्तों के जरिए पात्र महिलाओं के खातों में 63 हजार 248 करोड़ रुपए से अधिक की राशि पहुंचाई जा चुकी है। सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 में योजना के लिए 23 हजार 882.81 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया है। राजनीतिक दृष्टि से देखें तो मप्र में अगले तीन सालों में क्रमशः नगरीय निकाय और पंचायत फिर विधानसभा चुनाव और उसके बाद लोकसभा के चुनाव होंगे। प्रदेश में कुल महिला मतदाताओं की संख्या 2 करोड़ 60 लाख से अधिक है, जबकि लाड़ली बहना योजना से लाभान्वित महिलाओं की संख्या 1 करोड़ 25 लाख से कुछ कम है। इसी तरह लाड़ली लक्ष्मी योजना के हितग्राहियों की संख्या करीब 53 लाख है। दोनों मिला लें तो यह तादाद पौने 2 करोड़ होती है, जो कुल महिला मतदाताओं की संख्या का लगभग 70 फीसदी होती है। अगर इसमें से 80 प्रतिशत वोट भी एकतरफा पड़ जाएं तो चुनाव का नतीजा बदल सकता है। 2023 के विधानसभा चुनाव में लाड़ली बहना योजना ने ही भाजपा की सत्ता में वापसी कराई थी। जब उस वक्त माना जा रहा था कि लंबे समय से सत्ता में रही सरकार के खिलाफ एंटी इकम्बेंसी चरम पर है। लाडली बहना के रूप में शिवराज ने न केवल भाजपा बल्कि सभी राज्य सरकारों को चुनाव जीतने का एक शर्तिया फार्मूला हाथ में दे दिया। जिसमें एक बंगाल को छोड़ दें तो अधिकांश राज्यों के विधानसभा चुनावों में सफलता से प्रयोग हुआ है। बंगाल में तत्कालीन सीएम ममता बैनर्जी ने भी इसी तरह की योजना पहले से चला रखी थी, लेकिन उनके खिलाफ मतदाताओं की नाराजगी इतनी ज्यादा थी कि नकद सहायता योजना भी उनकी सरकार नहीं बचा सकी। आर्थिक दृष्टि से देखें तो हर माह बिना किसी मेहनत के बैंक खाते में आने वाली यह छोटी सी राशि भी गरीब महिलाओं के लिए अमृत समान है।

नजरिया

संजय सक्सेना

लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।

झारखंड छात्र आंदोलन में सीबीआई जांच न करवाने के मायने

छात्रों के भारी दबाव के बाद झारखंड सरकार ने जिन प्रमुख परीक्षाओं को रद्द किया है, उनमें सबसे बड़ी जेएसएससी-सीजीएल परीक्षा शामिल है। इसके अलावा, एक विवादित और दागी आउटसोर्सिंग एजेंसी 'टीआरएस डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड' (टीडीपीएल) के जरिए वर्ष 2014 से लेकर अब तक जितनी भी परीक्षाएं आयोजित की गई थीं, उनके परिणाम जारी हुए थे या जिन अभ्यर्थियों का चयन हुआ था, उन सभी प्रक्रियाओं को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया है। इतना ही नहीं, सरकार ने इससे पहले ही छात्रों के भारी विरोध को देखते हुए 14वीं झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) की प्रारंभिक परीक्षा और वर्ष 2023 और 2025 में आयोजित जेपीएससी की बैकलॉग परीक्षाओं को भी रद्द करने का फैसला लिया था। इन परीक्षाओं में बड़े पैमाने पर प्रश्नपत्र लीक होने, डिजिटल धांधली करने और पैसों के लेन-देन के गंभीर आरोप लगे थे, जिसके बाद तीन जेपीएससी सदस्यों को अपने पदों से इस्तीफा तक देना पड़ा था।

झारखंड में छात्रों के चौतरफा और ऐतिहासिक आंदोलन के आगे आखिरकार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार झुक गई है और उसने राज्य की सबसे विवादित झारखंड कर्मचारी चयन आयोग-संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा को रद्द करने के साथ ही साल 2014 से अब तक निजी एजेंसी टीडीपीएल द्वारा ली गई सभी भर्ती परीक्षाओं और नियुक्तियों को पूरी तरह खारिज कर दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कैबिनेट की एक मैराथन बैठक बुलाई और इस बड़े फैसले पर मुहर लगा दी। छात्रों की इस अभूतपूर्व जीत के बाद राज्य भर के परीक्षा केंद्रों और प्रदर्शन स्थलों पर जश्न का माहौल है, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में एक बड़ा पेंच अभी भी फंसा हुआ है। छात्र संगठन इस पूरे घोटाले की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई जांच की मांग पर अड़े हुए हैं, जिसे राज्य सरकार ने फिलहाल सिरे से खारिज कर दिया है। मुख्यमंत्री सोरेन ने इस पूरे मामले की कमान राज्य की अपराध अनुसंधान विभाग और विशेष जांच दल को सौंपते हुए वर्ष 2014 से हुई गड़बड़ियों की व्यापक जांच का आदेश दिया है, लेकिन वह केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार से सीबीआई जांच की सिफारिश करने से साफ बच रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों और जानकारों का मानना है कि राज्य सरकार को डर है कि अगर यह जांच सीबीआई के हाथों में चली गई, तो जांच की आंच सीधे सरकार के शीर्ष अधिकारियों और सत्ता के गलियारों तक पहुंच जाएगी, जिससे उनकी राजनीतिक गर्दन पूरी तरह से दिल्ली में बैठी केंद्र सरकार के हाथों में आ जाएगी।

इस पूरे विवाद की जड़ में वह परीक्षाएं हैं, जिन्हें लेकर पिछले कई महीनों से राज्य का युवा सड़कों पर उतरा हुआ था। छात्रों के भारी दबाव के बाद झारखंड सरकार ने जिन प्रमुख परीक्षाओं को रद्द किया है, उनमें सबसे बड़ी जेएसएससी-सीजीएल परीक्षा शामिल है। इसके अलावा, एक विवादित और दागी आउटसोर्सिंग एजेंसी 'टीआरएस डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड' (टीडीपीएल) के जरिए वर्ष 2014 से लेकर अब तक जितनी भी परीक्षाएं आयोजित की गई थीं, उनके परिणाम जारी हुए थे या जिन अभ्यर्थियों का चयन हुआ था, उन सभी प्रक्रियाओं को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया है। इतना ही नहीं, सरकार ने इससे पहले ही छात्रों के भारी विरोध को देखते हुए 14वीं झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) की प्रारंभिक परीक्षा और वर्ष 2023 और 2025 में आयोजित जेपीएससी की बैकलॉग परीक्षाओं को भी रद्द करने का फैसला लिया था। इन परीक्षाओं में बड़े पैमाने पर प्रश्नपत्र लीक होने, डिजिटल धांधली करने और पैसों के लेन-देन के गंभीर आरोप लगे थे, जिसके बाद तीन जेपीएससी सदस्यों को अपने पदों से इस्तीफा तक देना पड़ा था। सरकार ने अब परीक्षाओं के आयोजन में सुधार लाने और पूरी व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अमिताभ कौशल के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय परीक्षा सुधार समिति का गठन भी कर दिया है।

पिछले 24 दिनों का घटनाक्रम झारखंड के इतिहास में युवाओं के सबसे बड़े और संगठित विद्रोह की कहानी बयां करता है। आंदोलन की शुरुआत जुलाई के आखिरी हफ्तों में हुई थी, जब जेएसएससी-सीजीएल परीक्षा के आयोजन और उसके नतीजों में भारी विसंगतियां और धांधली के सबूत सोशल मीडिया पर तैरने लगे थे। इसके बाद छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने रांची की सड़कों पर उतरकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन शुरू कर दिया। देखते ही देखते इस आंदोलन ने एक उग्र रूप ले लिया और छात्र नेताओं ने जयपाल सिंह स्टेडियम और अन्य प्रमुख स्थलों पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। पिछले दो हफ्तों से छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो और राहुल क्रांति समेत कई अन्य अभ्यर्थी आमरण अनशन पर बैठ गए थे। भूख हड़ताल की वजह से कई छात्रों की तबीयत इस कदर बिगड़ गई कि उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। इसके बावजूद छात्रों का हौसला नहीं डगमगाया और उन्होंने सरकार से साफ कह दिया कि जब तक परीक्षाएं रद्द नहीं होंगी और पारदर्शी जांच की गारंटी नहीं मिलेगी, वे पीछे नहीं हटेंगे। छात्रों ने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने और राज्य विधानसभा तक एक विशाल पैदल मार्च निकालने का भी एलान कर दिया था, जिसने सोरेन सरकार के भीतर एक राजनीतिक घबराहट पैदा कर दी थी।

आंदोलन के बढ़ते दबाव और छात्रों की बिगड़ती सेहत को देखते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अपने मंत्रियों के साथ एक आपातकालीन बैठक करनी पड़ी। इस बैठक में राज्य के खुफिया इनपुट और पुलिस विभाग की रिपोर्ट को सामने रखा गया, जिसमें यह साफ हो गया था कि छात्रों का यह गुस्सा राज्य सरकार के लिए आगामी चुनावों में भारी नुकसानदेह साबित हो सकता है। इसके बाद मुख्यमंत्री ने खुद सामने आकर घोषणा की कि सीआईडी और एसआईटी की जांच में कुछ बेहद चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं, जिन्हें इस मोड़ पर उजागर नहीं किया जा सकता। उन्होंने माना कि परीक्षाओं का संचालन करने वाली बाहरी एजेंसियां एक बड़े रैकेट का हिस्सा हैं, जो झारखंड के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही थीं। सरकार ने तुरंत टीडीपीएल को ब्लैकलिस्ट करते हुए उसके द्वारा कराए गए पिछले दस साल के सभी कामों को शून्य घोषित कर दिया। मंत्रियों की मौजूदगी में अस्पताल में भर्ती अनशनकारी छात्रों को जूस पिलाकर उनका अनशन खत्म कराया गया, जिसे छात्र संगठनों ने अपनी आधी और ऐतिहासिक जीत माना।

हालांकि, परीक्षाओं के रद्द होने से आंदोलन पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, बल्कि इसने एक नया राजनीतिक और कानूनी मोड़ ले लिया है। छात्र संगठन और विपक्षी दल अब भी इस बात पर अड़े हैं कि राज्य की सीआईडी या एसआईटी इस विशाल सिंडिकेट और उसके असली सरगनाओं को कभी नहीं पकड़ पाएगी। छात्रों का तर्क है कि जब तक इस पूरे मामले की जांच देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई नहीं करेगी, तब तक पर्दे के पीछे बैठे असली 'मास्टरमाइंड' और सफेदपोश राजनेता कभी बेनकाब नहीं होंगे। दूसरी तरफ, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का सीबीआई जांच से इनकार करना उनकी राजनीतिक मजबूरी और केंद्रीय एजेंसियों के डर को दर्शाता है। सोरेन सरकार का मानना है कि केंद्र की भाजपा सरकार सीबीआई का इस्तेमाल विपक्षी दलों को कुचलने और राज्य सरकारों को अस्थिर करने के लिए एक राजनीतिक हथियार के रूप में करती रही है। मुख्यमंत्री खुद भूमि घोटाले से जुड़े एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद महीनों जेल में बिताकर हाल ही में जमानत पर बाहर आए हैं। ऐसे में वे भली-भांति जानते हैं कि अगर उन्होंने इस परीक्षा घोटाले की चाबी सीबीआई को सौंप दी, तो केंद्र सरकार इस जांच का दायरा बढ़ाकर उनके करीबियों और सरकार के मंत्रियों तक पहुंचा देगी, जिससे पूरी सरकार संकट में आ सकती है।

मुद्दा

डॉ. सत्येंद्र किशोर मिश्र

प्रोफेसर अर्थशास्त्र, सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय, उज्जैन

भारत में दिमागी नक्सल: वास्तविकता या मिथक

भारतवर्ष वैश्विक पटल पर विकसित तथा मजबूत राष्ट्र बनने की कोशिश में अवश्य है, परन्तु सामने दिमागी नक्सल जैसी प्रतिक्रियावादी वैचारिक अराजकता से निपटने की चुनौती भी है। सांस्कृतिक मार्क्सवाद, नव-मार्क्सवाद, पाश्चात्य मार्क्सवाद, अस्तित्ववादी मार्क्सवाद जैसे विभिन्न नामों से उल्लेखित वैचारिक सोच का एक नाम दिमागी नक्सल भी है। प्रधानमंत्री के अनुसार हिंसक नक्सलवाद के सफाए के बाद इसके वैचारिक समर्थक दिमागी नक्सल, हिंसा तथा अराजकता का माहौल बनाने के अवसर तलाश रहे हैं। दिमागी नक्सल सत्ता से सिर्फ प्रत्यक्ष ही नहीं लड़ते, बल्कि वे व्यवस्था में अंदर तक घुसकर राष्ट्र के सामाजिकार्थिक तथा राजनैतिक तानेबाने को प्रभावित तथा नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं। दिमागी नक्सल, राजनैतिक रूप से संवेदनशील वर्ग में दृश्य-अदृश्य एक्टिविस्ट, शिक्षाविद, बुद्धिजीवी तथा आलोचक के रूप में सक्रिय रहकर शैक्षणिक परिसरों, मीडिया संस्थानों, सोशल मीडिया, सिविल सोसाइटी, संचार एवं प्रचार माध्यमों जैसे अनेक संस्थानों में अक्सर विद्वेष, घृणा, अराजकता एवं हिंसा जैसे हथकंडे अपनाकर सामाजिक तनाव उत्पन्न करते हैं। असल में दिमागी नक्सल, संस्कृति पर वैचारिक मार्क्सवाद तथा अराजकता को थोपने केसिवाय कुछ भी नहीं है। इनके परिस्थिकी तंत्र की पहचानकर इन्हें अलग-थलग करने की जरूरत है।

दिमागी नक्सल, एक ऐसी अराजक वैचारिक सोच है, जो संस्कृति तथा परंपरा को समाज में शोषण तथा उत्पीड़न का मुख्य कारण मानती है। इसे मार्क्सवाद की मूल अवधारणा तथा समय के साथ उसके वैचारिक बदलावों के संदर्भों में समझा जा सकता है। हेगेल मानव इतिहास को विपरीत विचारों के मध्य तनाव को सुलझाने की इच्छा के तौर पर समझते थे। हेगेल से प्रेरित कार्ल मार्क्स के लिए, ईश्वर, मानव मस्तिष्क के बाहर नहीं है, बल्कि यह मानव मस्तिष्क की कल्पना मात्र है। सर्वहारा समाज के शोषण से मुक्ति हेतु, मनुष्य को सामूहिक रूप से ईश्वर तथा धर्म में विश्वास को हटाकर शोषक निजी संपत्ति के कारण उत्पन्न आर्थिक टकराव को समझना होगा।

दिमागी नक्सल पारंपरिक मार्क्सवाद से इतर सामाजिक दर्शन पर आधारित होता है। इटली के प्रसिद्ध नव-मार्क्सवादी एंटोनियो ग्राम्शी ने अपने हेजेमनी (प्रभुत्व) के सिद्धांत में इतिहास को शोषक एंव शोषित के मध्य वर्ग-संघर्ष के रूप में स्वीकार तो किया, परन्तु वे मार्क्स के हिंसक वर्ग-संघर्ष तथा क्रांति को बेअसर मानते हैं। ग्राम्शी के नव-मार्क्सवाद के अनुसार पूंजीवाद और धर्म के प्रभुत्व को समाप्त करने हेतु पहले, मोर्चाबंदी कर सांस्कृतिक संस्थाओं पर कब्जा करना होगा। ग्राम्शी ने असल समस्या सिविल सोसाइटी जैसे परिवार, धर्मस्थल, श्रमिक संगठनों, शिक्षा संस्थानों में रचे-बसे सांस्कृतिक विचारों को माना। ग्राम्शी राज्य को मात्र बाहरी संरचना है, परन्तु इसके पीछे संस्कृति का एक शक्तिशाली तंत्र खड़ा रहता है। उनके अनुसार जब तक संस्कृति का प्रभुत्व नहीं टूटता, न तो मार्क्सवादी क्रांति आ सकती है और न ही आदर्श समाज की स्थापना हो सकती है। समस्या यह है कि संस्कृति ही, श्रमिक वर्ग के विद्रोह को रोकती है। मौलिक रूप से मार्क्स को गलत तथा हेगेल को सही मानते हुए, ग्राम्शी ने मार्क्स के विचार को उलट दिया। संस्कृति, अर्थव्यवस्था पर नहीं, बल्कि अर्थव्यवस्था, संस्कृति पर आश्रित होती है। यदि समाज की आर्थिक संरचना को बदलना है, तो सर्वप्रथम संस्कृति को बदलना होगा जो, लोगों में पूंजीवादी सोच और व्यवहार तैयार करती हैं। ग्राम्शी के अनुसार ऐसा करने का एकमात्र तरीका है, लोगों को उनकी परंपरा तथा संस्कृति से दूर किया जाए। अतः नव-मार्क्सवाद का मकसद सामाजिक संस्थाओं में घुसपैठ कर संस्कृति को खोखला कर इसे साम्यवादी वर्चस्व से प्रतिस्थापित करना है।

नव-मार्क्सवाद विचारक थियोडोर एडोर्नो, इतिहास की मार्क्सवादी व्याख्या तथा फ्रायड के मनोविज्ञान सहित अन्य विचारों को समन्वित कर संस्कृति तथा धर्म आधारित समाज की व्याख्या करते हुए बताते हैं कि तानाशाह अक्सर उस समाज में देखे जाते हैं जो पारंपरिक पितृसत्तात्मक पारिवारिक ढांचे को बढ़ावा देते हैं, लैंगिक आजादी का दमन करते हैं। वहीं फ्रैंकफर्ट स्कूल के प्रमुख विचारक मार्क्यूज के अनुसार सांस्कृतिक मार्क्सवाद सही मायने में एक ऐसी सांस्कृतिक क्रांति है, जो पारंपरिक संस्कृति तथा मौजूदा सामाजिक एवं नैतिक मूल्यों के विरूद्ध होती है। क्रांति के पारंपरिक विचार तथा रणनीति तभी कारगर हो सकती, जब कि सांस्कृतिक व्यवस्था तथा पारंपरिक नैतिक मूल्यों को जड़ से उखाड़ फेंका जाए। मार्क्यूज को सामाजिक बदलाव के लिए कामगार वर्ग पर भरोसा नहीं था, क्योंकि यह वर्ग समय के साथ पूँजीवादी संस्कृति एवं व्यवस्था में घुल-मिल जाता है। फिल्म, रेडियो तथा टेलिविजन ब्रॉडकास्टिंग, समाचार पत्र तथा पत्रिकाएं, विज्ञापन तथा व्यावसायिक जरूरतों से नियंत्रित होकर, उपभोक्तावादी पूंजीवाद की गुलामी करते हैं। इसलिए कुछ ऐसे अन्य समूह, जो पूंजीवादी संस्कृति एवं व्यवस्था से थोड़े कम जुड़े होते हैं, वे चिंगारी का काम कर सकते हैं; जैसे छात्र, बुद्धिजीवी तथा अल्पसंख्यक समूह। ऐसे वर्गों को सांस्कृतिक मार्क्सवाद के केन्द्र में रखना जरूरी है।

सांस्कृतिक मार्क्सवाद द्वारा अपनाए गए सिद्धांतों में उत्तर-आधुनिकतावाद (पोस्टमॉडर्निज्म) भी है, जिसमे संस्कृति तथा पूर्ण आध्यात्मिक सत्य को नकारना भी शामिल है। इसके अनुसार संस्कृति तथा सभ्यता असल में अन्याय, उत्पीड़न, आक्रामकता, नस्लवाद, गुलामी, वर्गविभेद तथा लैंगिक दमन इत्यादि के लिए जिम्मेदार होती है। फ्रैंकफर्ट स्कूल द्वारा विकसित सांस्कृतिक मार्क्सवाद का एक अन्य सिद्धांत क्रिटिकल थ्योरी, सामाजिक आलोचना का एक तीखा रूप है, जिसका मकसद मौजूदा हालात को बेहतर बनाने की उम्मीद में उन्हें बदलकर एक ऐसे समाज की स्थापना करना है, जिसमे सभी की जरूरतें पूरी हो तथा उनके सपने साकार हों। यह असल में एक नकारात्मक प्रतिक्रिया है, जो निराशावादी सोच को दिखाती है। इसमे संस्कृति के उन पहलुओं की तीखी और लगातार आलोचना की गई जिन्हें यह दमनकारी या अमानवीय मानता है, परन्तु बदले में कोई ठोस विकल्प नहीं देता। सांस्कृतिक मार्क्सवाद में ऐसा कोई विचार नहीं है जो वर्तमान तथा भविष्य की व्यवस्था के मध्य अंतराल को भर सके। कोई सार्थक प्रयास भी नहीं हुए, तो सफलता भी नहीं दिखी, यह नकारात्मक बनी रही। नकारात्मकता इस हद तक दिखती है कि यह मान लिया गया कि बड़े पैमाने पर सामाजिक बदलाव की संभावना को कभी बर्बरतापूर्वक तथा कभी प्रचारतंत्र द्वारा कुचला जा सकता है। वस्तुतः सांस्कृतिक मार्क्सवाद उन लोगों से जुड़ना चाहता है, जो नकारात्मकता तथा निराशावाद में नाउम्मीदी में ही जीना चाहते हैं।

सांस्कृतिक मार्क्सवादी विचारकों को इसकी सफलता पर भरोसा कम तथा संदेह अधिक रहा है। एडोर्नो ने छात्र समूहों पर अतिवादी तथा फासीवादी व्यवहार का आरोप लगाया। जिसमें बातचीत या समझौते के लिए बुलाना, और फिर उसमे नामुमकिन शर्त सम्मिलित कर देना तथा ऐसे अशोभनीय बर्ताव करना जो आंदोलन या क्रांति को ही संदेहास्पद बना देती है। उन्होंने बड़े आंदोलनों को पागलपन का नाटक बताया जिसका अंजाम तानाशाही होती है। मार्क्यूज को यह विरोधाभासी भी दिखी, उनका यह मानना कि क्रांतिकारी अल्पसंख्यकों को बहुसंख्यकों की राय को दबाने का अधिकार है, वस्तुतः न सिर्फ अलोकतांत्रिक तथा अपने आप में गलत है, जो वैचारिक अभिव्यक्ति का संकट भी बन सकता है।

दिमागी नक्सल न तो मिथक है और न ही गलत नाम, भारत के संदर्भ में तो बिल्कुल भी नहीं। आज दक्षिण एशिया में भारतवर्ष के सीमाई देशों में सत्ता विरोधी आंदोलन तथा अराजक माहौल के साथ-साथ अनेक ताकतें, इनको खाद-पानी दे रही हैं। देश के अंदर अनेक दबाव समूहों का भरोसा भी लोकतांत्रिक मूल्यों पर डगमगाता रहा है। सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषाई, भौगोलिक तथा जनांकिकीय संरचना का समय-समय पर उपयोग निहित स्वार्थों द्वारा विघटन तथा अराजकता उत्पन्न करने हेतु होता रहा है। प्रतिक्रियावादी शक्तियों द्वारा लोकतांत्रिक मूल्यों तथा तरीकों के दुरूपयोग का भारत में इतिहास रहा है। मजबूत होते सांस्कृतिक, आध्यात्मिक तथा आर्थिक पुनरूत्थान की वैश्विक प्रतिक्रिया भी स्वाभाविक है।

वर्तमान, आशावादी संस्कृति तथा प्रतिक्रियादी आधुनिक सोच के मध्य टकराव का यह दौर है। आज देश के सांस्कृतिक मूल्यों को बेहतर ढ़ंग से समझने तथा समझाने की जरूरत है। भारत में सांस्कृतिक विरासत, सामाजिक संस्थाओं, आध्यात्मिक तथा नैतिक मूल्यों एवं नागरिक कर्तव्यों को मजबूत करना होगा। साथ ही प्रतिक्रियावादी, नकारात्मक तथा निराशावादी प्रश्नों के जवाब देने की भी जिम्मेदारी है। कभी यह जिम्मेदारी थोड़ी बहुत अराजकता तथा हिंसा की ओर ले जा सकती है, अन्ततः व्यवस्था में सुधार तथा देश की बेहतरी की ओर ही ले जाएगी।

वस्तुतः भारत में दिमागी नक्सलवाद प्रतिक्रियावादी सिद्धांत है, जो भावनात्मकता तथा अराजक बौद्धिकता का भारत के सांस्कृतिक मूल्यों से टकराव का परिणाम है। ऐसे में सांस्कृतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक मुद्दों पर सार्थक विमर्श जरूरी है। आसन्न चुनौतियों तथा समस्याओं के असल कारणों को बेहतर ढंग से समझा जाए। भले ही आज का माहौल उथल-पुथल भरा है, फिर भी, व्यवस्था की जिम्मेदारी है कि लोगों के जीवनस्तर में सुधार के प्रयास के साथ-साथ अभिव्यक्ति की आजादी बरकरार रहे। बढ़ती जनाकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, सांस्कृतिक विरासत को सहेजने, शासन में पारदर्शिता तथा उत्तरदायित्व, नागरिक गरिमा की रक्षा तथा सामाजिक न्याय की बेहतरी हेतु अभी बहुत कुछ करना शेष है।

स्वामी, सुबह सवेरे मीडिया एल.एल.पी. के लिए उमेश त्रिवेदी द्वारा पंकज प्रिंटर्स एंड पैकेजिंग, 16, अल्फा इंडस्ट्रीयल पार्क, जाखिया, इंदौर, म.प्र.-453555 से मुद्रित एवं 662, साई कृपा कॉलोनी, बॉम्बे हॉस्पिटल के सामने, इंदौर से प्रकाशित।

प्रधान संपादक
उमेश त्रिवेदी
कार्यकारी प्रधान संपादक
अजय बोकिल
संपादक (मध्यप्रदेश)
विनोद तिवारी
स्थानीय संपादक
हेमंत पाल
प्रबंध संपादक
रमेश रंजन त्रिपाठी

(सभी विवादों का न्याय क्षेत्र इंदौर रहेगा)
RNI No. MPHIN/ 2015/ 66040,
Mobile No.: 09893032101
Email- subahsaverenews@gmail.com

'सुबह सवेरे' में प्रकाशित विचार लेखकों के निजी मत हैं। इनसे समाचार पत्र का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

व्यंग्य

सुधीर नायक

लेखक व्यंग्यकार हैं।

हलुए वालों को उठती चने की चुल....

लोग कितना भी महिमा मंडन करते रहें पर सच्ची बात तो यह है कि पुरस्कार बेवकूफों के लिए होते हैं,जो कुछ कमा नहीं पाये,जो कुछ जमा नहीं पाये। जो बिना पैसे वाले फालतू कामों में लगे रहे। लिखना-पढ़ना, सेवा टाइप के काम। शब्दकोष बनाने वालों ने अर्थ का अर्थ पैसा भी बताया और मीनिंग भी बताया। उनका मैसेज साफ़ है। 'अर्थ' है तो जीवन का कुछ अर्थ है। नहीं तो सब व्यर्थ है। समाज ऐसे व्यर्थ लोगों का भी ख्याल रखता है। उनके लिए यह इंतजाम किया गया है। उसे पुरस्कृत कर दो मतलब कुछ दे दिलाकर फुर्सत कर दो। उसने कुछ मज़ा नहीं लिया तो उसे हमने यह मुआवजा दिया। पुरस्कार एक तरह का शुकराना है। अगर वह आदमी भी पैसे कमाने लगता तो दूसरे कमाने वालों का हिस्सा कम होता। लेकिन वह आड़े नहीं आया। उसने वॉकओवर दे दिया। तो समझो कि यह उसकी फीस है,बख्शीश है। या फिर दौड़ में पिछड़ गया। दौड़ा तो था पर भीड़ इतनी थी कि नंबर नहीं लग पाया। धक्के खाकर गिर गया। कुचला गया,रौंदा गया। यह टूट-फूट का हर्जाना है। इसमें कुछ-कुछ करुणा भी छुपी है। अभागा निकला। इसे कुछ दे दो। उसकी बेवकूफी सलामत रहे-यह भाव भी निहित है। इससे समाज को फायदा है। उसे पुरस्कृत होते देखकर कुछ और लोग उसी की राह पर चल पड़ते हैं। इससे काम्प्टीशन घटता है। भीड़ कम होती है। पैसे कमाने वालों का सफर आसान हो जाता है। ट्रैफिक जाम न हो तभी अंजाम अच्छा होता है। लेकिन,अब ग़लत चलन चल पड़ा है। पैसे वाले पुरस्कारों के फील्ड में आ रहे हैं। वे जीवन भर पैसे पर फोकस रहे। अब वे पुरस्कार भी लेना चाहते हैं। पचास के आसपास पुरस्कार की तीव्र चुल उठती है। मन थोड़ा एडवेंचर चाहता था। अब वे पुरस्कार का शिकार करना चाहते हैं। सबकुछ तो झटक लिया एकाध पुरस्कार भी पटक लें। लेकिन इससे उनका ही नुकसान है। तुम पुरस्कार की तरफ आओगे तो पुरस्कार वाले तुम्हारे पैसे की तरफ जा सकते हैं। फिर क्या करोगे? दिक्कत तुम्हीं को होगी। पैसे की मेनका को पुरस्कार के विश्वामित्र की ओर क्यों रवाना करते हो? और फिर तुम पुरस्कार चाहते ही क्यों हो? पुरस्कार में धरा क्या है? अच्छा भला समझदारी का जीवन जिया। तुमने ऐसी कोई बेवकूफी की ही नहीं, जिसके लिए पुरस्कार मिले। मझले सेठजी को ही ले लो। मेरे पीछे बहुत दिन से पड़े थे। भाई,सुना है तुम्हारी अच्छी मारपकड़ है। मेरे लिए किसी पुरस्कार की जुगाड़ करो न। वे भोले-भाले हैं। उन्हें पुरस्कारों की एबीसीडी नहीं पता। उन्हें यह भी नहीं पता कौन पुरस्कार देसी है और कौन विदेशी। बोले-वो कोई मैंग से से होता है। उसी का जमाओ। लेंगे तो अपन रेमन मैग्सेसे ही लेंगे। तुम चिंता मत करना।से से के हम ठोककर पैसे देंगे। सेंतमेंत में नहीं लेंगे। टालते-टालते उस दिन मैं बिफर पड़ा। गुस्से में मेरे मुंह से निकल गया कि आपने समाज को दिया क्या है आपने? जो कुछ किया अपने लिए किया या फिर बड़े मुन्ना के लिए किया(बड़े मुन्ना उनके 'पुत्र' हैं)। आप आखिर किस बात का पुरस्कार लेना चाहते हैं? उनके भी तेवर बदल गये।

वे विनम्रता के खोल से बाहर आ गये। बोले-किसने कहा मैं लेना चाहता हूं? मैं तो खरीदना चाहता हूं। लेने और खरीदने में फर्क है,भाई। अब भाई,खरीदने पर तो कोई पाबंदी नहीं है। यह तो खुला बाजार है। जिसकी जेब में वज़न होगा वह खरीद लेगा। बाजार में चीज़ होगी तो ग्राहक तो मंडरायेंगे। और तुम देने की बात करते हो तो पैसे तो दे रहा हूं। मुफ्त में थोड़े ही ले रहा हूं। जिसके पास जो होगा वही तो देगा। मेरे पास पैसा है सो पैसा दे रहा हूं। तुम में हिम्मत हो तो मना कर दो पैसे को। मैं नरम पड़ गया। उनकी बात में वजन था। मैं उस वजन तले दब गया। मैंने मरी-मरी सी आवाज में कहा-लेकिन, भाई साहब, आपके पास भगवान का दिया सब कुछ तो है। इन पुरस्कारों के चक्कर में क्यों पड़ते हो? ये उन लोगों को रहने दो जिनके पास कुछ नहीं है। वे बोले- भाई, भले किसी इंसान ने दबाकर खाया हो पर पान की गिलौरी फिर भी दबाना चाहता है। भरे पेट वाला डकार लेता है भरे जेब वाला पुरस्कार लेता है। हलुआ खाते खाते कभी कभी चने चबाने का मन करता है। हलुए के बाद चना बहुत टेस्टी लगता है। तुम नहीं समझोगे। तुमने केवल चने ही चबाये हैं। मैं तो मुट्ठी दो मुट्ठी चबाऊंगा। फिर अपने हलुए पर लौट जाऊंगा। बाकी तो तुम्हीं लोगों को चबाना है। मैं कीमत दूंगा। उससे तुम लोग हलुआ चख लेना। तुम्हारा भी स्वाद बदल जायेगा। मुद्दा यह है चने चबाये जाते हैं और हलुआ खाया जाता है। तुमने अभी तक चबाना ही जाना है खाना नहीं जाना। खाना क्या होता है मैं तुम्हें बताऊंगा। और चबाना कैसे है यह तुम मुझे बता देना। मैं चुप हो गया।मुझे भी हलुए की प्लेट दिखने लगी थी।

कैसे-कैसे मंज़र सामने आने लगे हैं
हलुआ वाले चने की लाइन में लगे हैं।

अक्षय ऊर्जा दिवस पर विशेष

योगेश कुमार गोयल

लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।

ऊर्जा आत्मनिर्भरता की राह पर बढ़ता भारत

आज न केवल भारत में बल्कि समूची दुनिया के समक्ष बिजली जैसी ऊर्जा की महत्वपूर्ण जरूरतों को पूरा करने के लिए सीमित प्राकृतिक संसाधन हैं, साथ ही पर्यावरण असंतुलन और विस्थापन जैसी गंभीर चुनौतियां भी हैं। चर्चित पुस्तक 'प्रदूषण मुक्त सांसें' के अनुसार इन गंभीर समस्याओं और चुनौतियों से निपटने के लिए अक्षय ऊर्जा ही एक ऐसा बेहतरीन विकल्प है, जो पर्यावरणीय समस्याओं से निपटने के साथ-साथ ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने में भी कारगर साबित होगी लेकिन अक्षय ऊर्जा की राह में भी कई चुनौतियां मुंह बाये सामने खड़ी हैं। अक्षय ऊर्जा उत्पादन की देशभर में कई छोटी-छोटी इकाईयां हैं, जिन्हें एक ग्रिड में लाना बेहद चुनौतीपूर्ण कार्य है। इससे बिजली की गुणवत्ता प्रभावित होती है। भारत में अक्षय ऊर्जा के विविध स्रोतों का अपार भंडार मौजूद है लेकिन इनसे ऊर्जा उत्पादन करने वाले अधिकांश उपकरण विदेशों से आयात किए जाते हैं।

पृथ्वी पर ऊर्जा के परम्परागत साधन बहुत सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं, ऐसे में खतरा मंडरा रहा है कि यदि ऊर्जा के इन पारम्परिक स्रोतों का इसी प्रकार दोहन किया जाता रहा तो इन परम्परागत स्रोतों के समाप्त होने पर गंभीर समस्या उत्पन्न हो जाएगी। यही कारण है कि पूरी दुनिया में गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने की जरूरत महसूस की जाने लगी और इसी कारण अक्षय ऊर्जा स्रोतों से ऊर्जा जरूरतों की पूर्ति करने के प्रयास शुरू हुए। अक्षय का अर्थ है, जिसका कभी क्षय न हो अर्थात् अक्षय ऊर्जा वास्तव में ऊर्जा का असीम और अनंत विकल्प है और आज के समय में यह किसी भी राष्ट्र के अक्षय विकास का प्रमुख स्तंभ भी है। पिछले कुछ वर्षों से पर्यावरणीय चिंताओं को देखते हुए ऐसी ऊर्जा तथा तकनीकें विकसित करने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिनसे ग्लोबल वार्मिंग की विकराल होती समस्या से दुनिया को कुछ राहत मिल सके। किसी भी राष्ट्र को विकसित बनाने के लिए आज प्रदूषण रहित अक्षय ऊर्जा स्रोतों का समुचित उपयोग किए जाने की आवश्यकताभी है। देश में अक्षय ऊर्जा के विकास और उपयोग को लेकर जागरूकता पैदा करने के लिए ही वर्ष 2004 से हर साल 20 अगस्त को 'अक्षय ऊर्जा दिवस' भी मनाया जाता है।

आज न केवल भारत में बल्कि समूची दुनिया के समक्ष बिजली जैसी ऊर्जा की महत्वपूर्ण जरूरतों को पूरा करने के लिए सीमित प्राकृतिक संसाधन हैं, साथ ही पर्यावरण असंतुलन और विस्थापन जैसी गंभीर चुनौतियां भी हैं। चर्चित पुस्तक 'प्रदूषण मुक्त सांसें' के अनुसार इन गंभीर समस्याओं और चुनौतियों से निपटने के लिए अक्षय ऊर्जा ही एक ऐसा बेहतरीन विकल्प है, जो पर्यावरणीय समस्याओं से निपटने के साथ-साथ ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने में भी कारगर साबित होगी लेकिन अक्षय ऊर्जा की राह में भी कई चुनौतियां मुंह बाये सामने खड़ी हैं। अक्षय ऊर्जा उत्पादन की देशभर में कई छोटी-छोटी इकाईयां हैं, जिन्हें एक ग्रिड में लाना बेहद चुनौतीपूर्ण कार्य है। इससे बिजली की गुणवत्ता प्रभावित होती है। भारत में अक्षय ऊर्जा के विविध स्रोतों का अपार भंडार मौजूद है लेकिन इनसे ऊर्जा उत्पादन करने वाले अधिकांश उपकरण विदेशों से आयात किए जाते हैं। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) के अनुसार, कुछ साल पहले सौर ऊर्जा के लिए करीब 90 प्रतिशत उपकरण विदेशों से आयात किए गए थे, जिससे बिजली उत्पादन की लागत काफी बढ़ गई। अब भी भारत की सौर सेल और मॉड्यूल की जरूरत का अधिकांश हिस्सा आयात से ही पूरा हो रहा है। हालांकि हाल के वर्षों में एएलएमएम नियम और पीएलआई स्कीम के कारण यह निर्भरता घट रही है। 2023-24 में चीन से सौर सेल्स का 53 प्रतिशत और मॉड्यूल्स का 63 प्रतिशत भारत में आया। देश में ऊर्जा की मांग और आपूर्ति के बीच अंतर भी तेजी से बढ़ रहा है। देश में कुल स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता में अब बड़ा हिस्सा अक्षय ऊर्जा से प्राप्त हो रहा है, जिसमें सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायो-पावर और छोटे हाइड्रो प्रोजेक्ट्स शामिल हैं। इसके अतिरिक्त अधिक बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं से तथा परमाणु ऊर्जा से भी अक्षय ऊर्जा का उत्पादन किया जा रहा है। कुल बिजली उत्पादन में अब अक्षय ऊर्जा का हिस्सा अब लगातार बढ़ रहा है, जो भारत को दुनिया के अग्रणी देशों में शामिल करता है। भारत में ऊर्जा खपत भी तेजी से बढ़ रही है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (आईईए) का अनुमान है कि वर्ष 2040 तक भारत में ऊर्जा की कुल मांग वर्तमान की तुलना में लगभग दोगुनी हो जाएगी।

विशेषकर बिजली तथा ईंधन के रूप में उपभोग की जा रही ऊर्जा की मांग घरेलू एवं कृषि क्षेत्र के अलावा औद्योगिक क्षेत्रों में भी लगातार बढ़ रही है। औद्योगिक क्षेत्रों में ही बिजली तथा पैट्रोलियम जैसे ऊर्जा के महत्वपूर्ण स्रोतों का लगभग 55 प्रतिशत उपभोग किया जाता है।

हम जिस बिजली से अपने घरों, दुकानों या दफ्तरों को रोशन करते हैं, जिस बिजली या पैट्रोलियम इत्यादि ऊर्जा के अन्य स्रोतों का इस्तेमाल कर खेती-बाड़ी या उद्योग-धंधों के जरिये देश को विकास के पथ पर अग्रसर किया जाता है, क्या हमने कभी सोचा है कि वह बिजली या ऊर्जा के अन्य स्रोत हमें कितनी बड़ी कीमत पर हासिल होते हैं? यह कीमत न केवल आर्थिक रूप से बल्कि पर्यावरणीय दृष्टि से भी धरती पर विद्यमान हर प्राणी पर बहुत भारी पड़ती है। भारत में थर्मल पावर स्टेशनों में बिजली पैदा करने के लिए प्रतिदिन लगभग 18 लाख टन कोयले की खपत होती है। आज भी देश की लगभग 70 प्रतिशत से अधिक बिजली कोयले से ही पैदा होती है, शेष बिजली अक्षय ऊर्जा स्रोतों, जल, गैस व परमाणु ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त होती है।

दुनियाभर में ऊर्जा क्षेत्र में लगभग 75 प्रतिशत कार्बन उत्सर्जन बिजली उत्पादन से ही होता है। यही कारण है कि अब सौर ऊर्जा तथा पवन ऊर्जा जैसे अक्षय ऊर्जा स्रोतों को विशेष महत्व दिया जाने लगा है। अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार, यदि अक्षय ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता पर विशेष ध्यान दिया जाए तो वर्ष 2050 तक वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को 70 प्रतिशत तक घटाया जा सकता है। भारत ने भी 2030 तक 500 गीगावॉट गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा क्षमता हासिल करने और नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य वर्ष 2070 तक प्राप्त करने का संकल्प लिया है। अक्षय ऊर्जा स्रोतों के उपयोग को बढ़ावा देने से हमारी ऊर्जा की मांग और आपूर्ति केबीच का अंतर कम होता जाएगा और इससे प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से सामाजिक जीवन स्तर में भी सुधार होगा।

भारत में अब ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, स्मार्ट ग्रिड, बैटरी स्टोरेज और इलैक्ट्रिक मोबिलिटी जैसे कदम भी तेजी से आगे बढ़ाए जा रहे हैं, जो अक्षय ऊर्जा को व्यावहारिक और टिकाऊ बनाएंगे। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत वर्ष 2030 तक 5 मिलियन मीट्रिक टन उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है, जिससे भारत न केवल अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करेगा बल्कि निर्यातक देश भी बन सकेगा। सही मायने में अक्षय ऊर्जा ही आज भारत में विभिन्न रूपों में ऊर्जा की जरूरतों का प्रमुख विकल्प है, जो पर्यावरण के अनुकूल होने के साथ-साथ टिकाऊ भी है। भारत धीरे-धीरे ही सही, अब इस दिशा में आगे बढ़ रहा है और आज समय है कि हम आर्थिक बदहाली और भारी पर्यावरणीय विनाश की कीमत पर ताप, जल एवं परमाणु ऊर्जा जैसे पारम्परिक ऊर्जा स्रोतों पर निर्भर रहने के बजाय अपेक्षाकृत बेहद सस्ते और कार्बन रहित पर्यावरण हितैषी ऊर्जा स्रोतों के व्यापक स्तर पर विकास के मार्ग पर तेजी से आगे बढ़ें। साथ ही हमें ऊर्जा की बचत की आदतें भी अपनानी होंगी क्योंकि ऊर्जा का विवेकपूर्ण उपयोग ही हमें सुरक्षित, समृद्ध और स्वच्छ भविष्य की ओर ले जाएगा।

सामयिक

रविकांत राऊत

लेखक साहित्यकार हैं।

एक्सप्रेसवे पर सड़क नहीं, वादा धंसा है

आज सामने आई प्रारंभिक तकनीकी जाँच में एक दिलचस्प लेकिन चिंताजनक तस्वीर उभरी है। आईआईटी खड़गपुर के विशेषज्ञों ने पाया कि जिन जगहों पर सड़क धंसी, वहाँ मिट्टी में गहराई तक नमी के संकेत मिले हैं, और तकनीकी विशेषज्ञों का मानना है कि अर्थवर्क व ड्रेनेज लेयर मानकों के अनुरूप न होने पर लगातार बारिश के बाद पानी नीचे तक पहुँचकर सड़क की सतह को प्रभावित कर सकता है। हालाँकि डामर की गुणवत्ता शुरुआती जाँच में संतोषजनक पाई गई है। यानी दोष अकेले सामग्री का नहीं, बल्कि डिज़ाइन और जल-निकासी की बुनियादी इंजीनियरिंग सोच का लगता है , यह वह चीज़ है, जो किसी एक ठेकेदार की लापरवाही से ज़्यादा, पूरी निर्माण-प्रक्रिया की जल्दबाज़ी की ओर इशारा करती है।

13 जुलाई को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिलकर जिस 4,200 करोड़ रुपये के कानपुर-लखनऊ एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया था, वह उद्घाटन के 25वें दिन तक आते-आते 53 अलग-अलग जगहों पर धंस चुका था। 63 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे पर लोकार्पण के 25 दिन बाद भी सड़क सात जगह पर 108 मीटर तक धंस गई, और एनएचएआई के नए प्रोजेक्ट डायरेक्टर को खुद ग्रीनफील्ड क्षेत्र के 45 किलोमीटर हिस्से का निरीक्षण करने उतरना पड़ा। महीने भर के भीतर अगस्त के पहले पाँच दिनों में ही इस सड़क पर धंसाव, मिट्टी का कटाव, गड्ढे और मरम्मत की असफल कोशिशों की कई घटनाएँ दर्ज हुईं, जिससे इसके निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठने लगे।

आज सामने आई प्रारंभिक तकनीकी जाँच में एक दिलचस्प लेकिन चिंताजनक तस्वीर उभरी है। आईआईटी खड़गपुर के विशेषज्ञों ने पाया कि जिन जगहों पर सड़क धंसी, वहाँ मिट्टी में गहराई तक नमी के संकेत मिले हैं, और तकनीकी विशेषज्ञों का मानना है कि अर्थवर्क व ड्रेनेज लेयर मानकों के अनुरूप न होने पर लगातार बारिश के बाद पानी नीचे तक पहुँचकर सड़क की सतह को प्रभावित कर सकता है। हालाँकि डामर की गुणवत्ता शुरुआती जाँच में संतोषजनक पाई गई है। यानी दोष अकेले सामग्री का नहीं, बल्कि डिज़ाइन और जल-निकासी की बुनियादी इंजीनियरिंग सोच का लगता है, यह वह चीज़ है, जो किसी एक ठेकेदार की लापरवाही से ज़्यादा, पूरी निर्माण-प्रक्रिया की जल्दबाज़ी की ओर इशारा करती है।

असली सवाल यहीं खड़ा होता है। भारत बीते एक दशक में हर साल हज़ारों किलोमीटर नए हाईवे जोड़ने का दावा करता आया है, और यह उपलब्धि वास्तविक भी है। लेकिन क्या रफ्तार के इस उत्सव में गुणवत्ता की जाँच उतनी ही गंभीरता से हो रही है, जितनी उद्घाटन की तैयारी होती है? कानपुर-लखनऊ एक्सप्रेसवे कोई अपवाद नहीं है। बिहार में 2020 से अब तक दर्जनों पुल गिर चुके हैं, जिनमें सबसे महँगा हादसा अगुवानी-सुल्तानगंज पुल का रहा, 1,710 करोड़ रुपये की लागत वाला यह पुल तीन बार ढह चुका है। मध्य प्रदेश में जबलपुर-भोपाल राष्ट्रीय राजमार्ग पर 400 करोड़ की लागत से बना रेलवे ओवरब्रिज चार साल भी पूरे नहीं कर पाया और गिर गया, जबकि उसका ठेकेदार पहले से ही ब्लैक लिस्टेड था। और खरगोन में भारतमाला परियोजना के तहत बना एक ब्रिज तो उद्घाटन से पहले ही धंस गया, जिसमें महज़ चार इंच कंक्रीट और 10 एमएम सरिये के इस्तेमाल की बात सामने आई।

यह तस्वीर उतनी सरल नहीं जितनी लगती है। यह मानना ग़लत होगा कि हर मामला भ्रष्टाचार या जानबूझकर की गई धोखाधड़ी का नतीजा है। एक्सप्रेसवे जैसे बड़े प्रोजेक्ट में भूगर्भीय स्थितियाँ, असामान्य मानसून, और नदी-तल के ऊपर से गुज़रती सड़क का जटिल डिज़ाइन - ये सब वास्तविक इंजीनियरिंग चुनौतियाँ हैं। सरकार का पक्ष यह भी है कि जवाबदेही तय करने की व्यवस्था मौजूद है । ठेकेदार कंपनी को 'नॉन-परफॉर्मर' घोषित कर टोल वसूली रोक दी गई है, स्वतंत्र निगरानी करने वाली इंजीनियरिंग फर्म को भी नोटिस दिया गया है, और जाँच के लिए स्वतंत्र तकनीकी संस्थान बुलाए गए हैं। संसद में भी सरकार ने स्वीकार किया कि घटिया काम के लिए ठेकेदारों से जुर्माना वसूला जाता है और ठेका रद्द होने पर सिक्योरिटी ज़ब्त की जा सकती है। यानी तंत्र पूरी तरह निष्क्रिय नहीं है, पर वह हमेशा हादसे के बाद ही सक्रिय होता है, पहले नहीं।

यहीं भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल की असली कमज़ोरी छिपी है जहां जवाबदेही प्रतिक्रियात्मक है, निवारक नहीं। थर्ड-पार्टी क्वालिटी ऑडिट, मिट्टी और ड्रेनेज की गहन जाँच, और स्वतंत्र निगरानी, ये सब उद्घाटन से पहले, निर्माण के दौरान होने चाहिए, न कि सड़क धंसने और सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद। जब किसी परियोजना का उद्घाटन उसकी असली परीक्षा से पहले हो जाता है, तो वह उद्घाटन नहीं, केवल एक फोटो-अवसर बनकर रह जाता है।

इस सबका सबसे बड़ा नुकसान उस आम यात्री को होता है जो हर दिन इन सड़कों पर भरोसा करके निकलता है, बिना यह जाने कि उसके पहियों के नीचे की ज़मीन कितनी मज़बूत है। एक एक्सप्रेसवे केवल कंक्रीट और डामर की पट्टी नहीं होता, वह एक वादा होता है कि सरकार ने उसकी सुरक्षा को गंभीरता से लिया है। जिस दिन यह वादा धंसता है, उस दिन असली नुकसान सड़क का नहीं, उस भरोसे का होता है जिस पर विकास की पूरी कहानी टिकी है।

आयोजन

मोहम्मद अबरार खान

फोटो जर्नलिस्ट

फोटोग्राफरों ने सहेजी दुनिया बदलने की सच्ची कहानियां

जी हां, फोटोग्राफी का सीधा-सादा मतलब है रोशनी से लिखना या रोशनी के जरिए तस्वीर बनाना। फोटोग्राफी शब्द दो यूनानी शब्दों से मिलकर बना है। 'फोटो' का मतलब रोशनी और 'ग्राफी' का मतलब लिखना या चित्र बनाना है। यानी आसान भाषा में कहें तो रोशनी से तस्वीर बनाना ही फोटोग्राफी है।

विश्व फोटोग्राफी दिवस सिर्फ तस्वीरें लेने वालों को याद करने का दिन नहीं है, बल्कि उन लोगों को सलाम करने का दिन भी है, जिन्होंने अपनी मेहनत, सोच और हुनर से दुनिया के खूबसूरत, मुश्किल और ऐतिहासिक पलों को हमेशा के लिए कैमरे में कैद कर दिया। वरना हम शायद कभी नहीं जान पाते कि दुनिया एसी हुआ करती थी।

तस्वीर के पीछे छिपी है लंबी कहानी- फोटोग्राफी की शुरुआत का श्रेय फ्रांस के जोसेफ निसेफोर निएप्स को दिया जाता है, जिन्होंने 1820 के दशक में दुनिया की पहली स्थायी तस्वीर तैयार की। इसके बाद लुई डागेर ने डागेरियोटाइप प्रक्रिया को विकसित किया और फोटोग्राफी को आगे बढ़ाया। विलियम हेनरी फॉक्स टैलबोट की कैलोटाइप प्रक्रिया ने एक नेगेटिव से कई तस्वीरें बनाने का रास्ता खोला। बाद में जॉर्ज ईस्टमैन कैमरा और रोल फिल्म को आम लोगों तक लेकर आए।

लेकिन फोटोग्राफी की कहानी यहां से शुरू नहीं होती। इसकी जड़ें प्रकाश और छवि को समझने के पुराने वैज्ञानिक प्रयासों तक जाती हैं। अरब वैज्ञानिक अबू अली अल-हसन इब्न अल-हैथम ने प्रकाशिकी और कैमरा ऑब्स्क्यूरा के सिद्धांतों पर महत्वपूर्ण काम किया था। उन्हें फोटोग्राफर कहना सही नहीं होगा, लेकिन उनके वैज्ञानिक काम ने आगे चलकर कैमरे और फोटोग्राफी के विकास की मजबूत नींव रखी।

पहिए ने दुनिया को गति और कैमरे ने दृष्टि दी- मानव सभ्यता की तरक्की में फोटोग्राफी का योगदान सिर्फ सुंदर तस्वीरों तक सीमित नहीं है। जिस तरह पहिए ने इंसान की भौतिक यात्रा को रफ्तार दी, उसी तरह कैमरे ने दुनिया को देखने, समझने और याद रखने का एक नया नजरिया दिया। युद्ध हो या आजादी की लड़ाई, आंदोलन हो या प्राकृतिक आपदा, खेल हो या राजनीति तस्वीरों ने हर दौर की सच्चाई को अपने अंदर समेटकर रखा है। आज हम इतिहास के कई पन्नों को सिर्फ पढ़ते नहीं, बल्कि तस्वीरों के जरिए देख भी सकते हैं।

पत्रकारिता की ताकत है बोलती तस्वीर- फोटो जर्नलिज्म ने खबरों को देखने और समझने का तरीका ही बदल दिया। कई बार एक तस्वीर वह बात कह देती है, जिसे समझाने के लिए हजारों शब्द भी कम पड़ जाएं। दुर्घटना, युद्ध, आंदोलन, राजनीति, खेल, पर्यावरण और आम आदमी की जिंदगी हर जगह फोटोग्राफर मौके पर मौजूद रहकर वह पल कैमरे में कैद करता है, जो बाद में इतिहास का हिस्सा बन जाता है।

विज्ञान से लेकर वन्यजीवों के जीवन तक कैमरे निभा रहा अहम किरदार - विज्ञान और चिकित्सा के क्षेत्र में फोटोग्राफी ने सूक्ष्म दुनिया से लेकर अंतरिक्ष तक को रिकॉर्ड करने में बड़ी भूमिका निभाई है। वहीं वन्यजीव फोटोग्राफरों ने जंगलों, दुर्लभ जानवरों और पक्षियों की ऐसी तस्वीरें दुनिया के सामने रखीं, जिनसे लोगों में प्रकृति और वन्यजीवों को बचाने की सोच मजबूत हुई। कला, संस्कृति, त्योहार, पहनावा, पुरानी इमारतें और अलग-अलग समाजों की जिंदगी भी तस्वीरों के जरिए दुनिया के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पहुंची। तकनीक बदली, लेकिन तस्वीर की अहमियत नहीं। आज मोबाइल कैमरा, डिजिटल कैमरा, ड्रोन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने फोटोग्राफी को बहुत आसान और व्यापक बना दिया है। लेकिन तस्वीर का असली मकसद आज भी वही है किसी खास पल को रोक लेना और उसे आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचा देना।

कैमरे के पीछे खड़े लोगों की कहानी भी समझनी होगी - फोटोग्राफी की चमक के पीछे फोटोग्राफरों की जिंदगी का संघर्ष भी छिपा है। खासकर फोटो जर्नलिस्टों के लिए हालात आसान नहीं हैं। कई बड़े अखबारों और मीडिया संस्थानों में पहले जहां पांच से सात फोटो जर्नलिस्ट हुआ करते थे, अब वहां उनकी संख्या घटकर दो या उससे भी कम रह गई है।

सैलरी भी कई जगह इतनी नहीं है कि एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर अपने महंगे कैमरे, लेंस और दूसरे इक्युपमेंट आसानी से खरीद सके। कई संस्थान अपने फोटोग्राफरों को जरूरी कैमरा और उपकरण भी उपलब्ध नहीं कराते। ऊपर से कैमरा या लेंस खराब होने का खतरा हमेशा बना रहता है और कई बार उसके नुकसान की भरपाई की जिम्मेदारी भी संस्थान नहीं लेते। मोबाइल के आने के बाद उनसे फोटोग्राफ भी कोई पैसे देकर नहीं लेता मुफ्त में ही वाटसएप पर मांग लेता है।

तकनीक जितनी आगे बढ़ी है, कैमरे और लेंस उतने ही महंगे होते गए हैं। ऐसे माहौल में नई पीढ़ी के युवाओं का फोटो जर्नलिज्म की तरफ आना भी कम हुआ है। बहुत से युवा सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपना भविष्य तलाश रहे हैं। इसमें संभावानाएं भी बहुत हैं। अपना हुनर दिखाने का खास प्लेटफार्म बन कर उभर रहा है सोशल मीडिया।

हालांकि कुछ संस्थान ऐसे भी हैं जो फोटोग्राफी और तस्वीर की क्वालिटी की अहमियत समझते हैं। वे अपने फोटोजर्नलिस्टों को आधुनिक कैमरे और नई तकनीक उपलब्ध करा रहे हैं, लेकिन ऐसे संस्थानों की संख्या अब गिनी-चुनी है।

सांस्कृतिक कार्यक्रम और आयोजन फोटोग्राफी में भी आया है बड़ा बदलाव- वेडिंग और इवेंट फोटोग्राफी में भी तकनीक का असर साफ दिखाई दे रहा है। बड़ी इवेंट कंपनियां बड़े ऑर्डर ले रही हैं और काम का दायरा बढ़ा है, लेकिन कई बार कैमरे के पीछे मेहनत करने वाले फोटोग्राफर को उसकी कला और मेहनत के मुताबिक मेहनताना नहीं मिल पाता।

आप कह सकते हैं कि फोटोग्राफी सिर्फ पेशा नहीं, एक जुनून है - दरअसल फोटोग्राफी सिर्फ नौकरी या कमाई का जरिया नहीं है। यह एक ऐसा शौक है, जिसे एक बार किसी को इसका जुनून लग जाए तो वह जिंदगी भर तस्वीरें खींचता रहता है। आज कई आईएएस, आईपीएस, आईएफएस अधिकारी, वैज्ञानिक, इंजीनियर और प्रकृति प्रेमी भी फोटोग्राफी को अपने शौक के तौर पर अपना रहे हैं और इस क्षेत्र में अच्छा नाम बना रहे हैं।

कुल मिलाकर फोटोग्राफी ऐसी विधा है, जिससे जुड़ने वाला इंसान समाज को कुछ न कुछ देकर ही जाता है। अगर कैमरा आपके हाथ में है और तस्वीर के पीछे कोई अच्छी सोच है तो इस सफर से जुड़े रहिए। कई बार तस्वीर से मिलने वाला सुकून उस कमाई की कमी को भी भुला देता है, जो शायद इस हुनर के मुताबिक मिलनी चाहिए थी। इसलिए इसके साथ आय का अन्य साधन भी जरूर बनाएं तभी आफ अपने मन का काम कर सकेंगे।

पहिए ने दुनिया को आगे बढ़ने की रफ्तार दी, लेकिन कैमरे ने उस सफर की कहानी को हमेशा के लिए सहेज लिया। यही फोटोग्राफी की सबसे बड़ी ताकत है।

खेल से एकजुटता- विश्व फोटोग्राफी दिवस के अवसर पर स्पोर्ट्स मिरर-1 की ओर से भोजपुर क्लब में फोटो जर्नलिस्ट और लीजेंड क्रिकेटरों के बीच बॉक्स क्रिकेट मैच आयोजित किया गया। इस मुकाबले में कैमरे के पीछे रहने वाले फोटो जर्नलिस्ट मैदान पर क्रिकेट खेलते नजर आए। आयोजन का उद्देश्य फोटोग्राफी के साथ खेल भावना, फिटनेस और आपसी मित्रता को बढ़ावा देना रहा। मुख्य अतिथि अरणेश्वर शरण सिंह देव ने सभी को सम्मानित किया।

दृष्टिकोण

राजेंद्र बज
लेखक स्तंभकार हैं।

नई पीढ़ी बनाम पुरानी पीढ़ी: एक नजरिया यह भी

यह सिलसिला सैकड़ो हजारों वर्षों से निरंतर चला आ रहा है। बीते दौर में तो पीढ़ी-दर-पीढ़ी आचार विचार और व्यवहार को लेकर आमतौर पर प्रचलित परंपराओं के अनुरूप ही चला जाता था। किंतु आज ऐसा कतई नहीं है। देखते ही देखते व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक, व्यवसायिक परिस्थितियों ही नहीं अपितु धार्मिक सांस्कृतिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में भी एक प्रकार से क्रांतिकारी परिवर्तन हो चुका है। लेकिन ऐसे परिवर्तन का दौर अभी थमा नहीं है। देखते ही देखते समय इस कदर परिवर्तित हो रहा है कि पीढ़ी-दर-पीढ़ी चली आ रही विभिन्न परंपरा तथा रीति-रिवाज भी निरंतर बदलते जा रहे हैं।

आजकल की नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी की अपेक्षा बेहतर बचपन, किशोरावस्था तथा युवावस्था को जी रही है। पुरानी पीढ़ी ने बीते दौर के संघर्ष और अभावों के बीच कैसे जीवन जिया है, कैसे परिवार का पालन पोषण किया है, किस प्रकार अपनी सभ्यता और संस्कृति के अनुरूप सामाजिक परिवेश में अपनी छवि बनाई है, या कि कितनी विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए कोई एक निश्चित मुकाम पाया है ? नई पीढ़ी इस तरह की गहराई में उतर सके, यह कहीं से कहीं तक संभव ही नजर नहीं आता। दरअसल नई पीढ़ी नई हवा में सांस ले रही है, इसलिए वह शायद इस विषय पर कुछ सोचना ही नहीं चाहती। वैसे भी यह बहुत स्वाभाविक है।

यह सिलसिला सैकड़ो हजारों वर्षों से निरंतर चला आ रहा है। बीते दौर में तो पीढ़ी-दर-पीढ़ी आचार विचार और व्यवहार को लेकर आमतौर पर प्रचलित परंपराओं के अनुरूप ही चला जाता था। किंतु आज ऐसा कतई नहीं है। देखते ही देखते व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक, व्यवसायिक परिस्थितियों ही नहीं अपितु धार्मिक सांस्कृतिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में भी एक प्रकार से क्रांतिकारी परिवर्तन हो चुका है। लेकिन ऐसे परिवर्तन का दौर अभी थमा नहीं है। देखते ही देखते समय इस कदर परिवर्तित हो रहा है कि पीढ़ी-दर-पीढ़ी चली आ रही विभिन्न परंपरा तथा रीति रिवाज भी निरंतर बदलते जा रहे हैं।

कहीं किसी परंपरा या रीति रिवाज को सिरे से खारिज कर दिया गया है तो कहीं नए-नए रीति रिवाज तथा परंपराओं का सूत्रपात होने लगा है। यह सिलसिला भी निरंतर नित नए-नए रूप में भावी पीढ़ी के समक्ष आता रहेगा। लेकिन पुरानी पीढ़ी एक लंबे समय से हर किसी क्षेत्र में एक बंधी बंधाई लीक पर चलती रही थी। सैकड़ो हजारों वर्षों तक हर किसी क्षेत्र या विषय को लेकर कोई एक स्पष्ट अवधारणा हुआ करती थी। जिसका कि पीढ़ी-दर-पीढ़ी परिपालन होने का क्रम निरंतर जारी था। विभिन्न परंपरा तथा रीति-रिवाज का बहुत शिद्दत के साथ परिपालन किया जाता था। सामाजिक परिवेश में उच्च स्तरीय आदर्श का परिपालन सामाजिक प्रतिष्ठा को सुनिश्चित किया करता था।

लेकिन तमाम वैज्ञानिक आविष्कार तथा खोज के चलते दुनिया भर के बाजार में तमाम तरह के भौतिक संसाधनों की भरमार हो गई। उधर हर तरह का व्यापार व्यवसाय स्थानीय से लेकर अंतरराष्ट्रीय बाजार को तलाशने लगा। विभिन्न यातायात तथा परिवहन के साधन संसाधन अत्र-तत्र-सर्वत्र विचरण करने लगे। हर वस्तु तथा सेवा का बाजार बहुत फलता फूलता गया। आजकल तो दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर अपने व्यापार व्यवसाय को राष्ट्रीय ही नहीं अपितु अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्थापित कर देना, कोई बड़ी बात नहीं मानी जाती। दरअसल तकनीकी संचार क्रांति ने रहन-सहन, आदत तथा स्वभाव को एक खुला आकाश सा दे दिया है।

हर एक साधन संसाधन को आदमी ने अपनी अनिवार्य, आरामदायक या फिर विलासिता पूर्ण आवश्यकता के रूप में शुमार कर लिया है। लेकिन अब इन हालातों के चलते दुनिया भर के बाजार में नित नए साधन-संसाधन उपलब्ध होने लगे है। जी कि आम आदमी की परिकल्पना से काफी परे थे, लेकिन इन साधन-संसाधनों को भी आदमी ने अपनी विभिन्न आवश्यकताओं में शुमार कर लिया। आज स्थिति यह है कि लगातार नई-नई वस्तुओं तथा सेवाओं का बाजार लगा है, और हर एक व्यापार अथवा कारोबार बहुत तीव्र गति के साथ फल फूल रहा है।

कल्पना करना कठिन नहीं है कि उक्त तमाम परिस्थितियों के चलते क्या हम नई पीढ़ी से पुराने ढर्रे पर जीवन जीने की कल्पना करें ? दरअसल अब हर क्षेत्र में इस कदर विकास की तीव्र गति नजर आती है कि नई पौध को पुरानी क्यारी तक सीमित रखना सर्वथा असंभव ही है। सवाल यह नहीं है कि नई पीढ़ी को अपनी सोच पुरानी पीढ़ी के अनुरूप रखना चाहिए या नहीं ? दरअसल यह सवाल ही सिरे से बेमानी है। हकीकत तो यह है कि बदलते दौर के बदलाव को कहीं से कहीं तक टाला ही नहीं जा सकता। आजकल की नई पीढ़ी विभिन्न मुद्दों तथा विषयो पर 'दो टूक' निर्णय लेने की इच्छा शक्ति से परिपूर्ण नजर आती है। अब यह अलग बात है कि पुरानी पीढ़ी को यह रास आए या नहीं ?

लोकतंत्र के पावन मंदिर में संवाद के सूत्र- मध्य प्रदेश विधानसभा के सलाहकार के रूप में पंकज शुक्ला ने कार्य आरंभ कर प्रमुख सचिव अरविंद शर्मा से भेंट की। इस अवसर पर अवर सचिव नरेंद्र मिश्रा भी उपस्थित थे।

90 की रफ्तार में इनोवा ने स्कूटी को उड़ाया

पिता की मौत, बेटा गंभीर ; कार में कंडोम और शराब की बॉटल मिली, ड्राइवर गिरफ्तार

भोपाल (नप्र)। भोपाल में एक तेज रफ्तार इनोवा कार ने स्कूटी सवार पिता-पुत्र को टक्कर मार दी। हादसे में 35 वर्षीय शुभम अवस्थी की मौत हो गई, जबकि उनका मासूम बेटा माधव गंभीर रूप से घायल है। घटना कोलार इलाके में अंकित परिसर के पास मंगलवार रात 12 बजे की है।

ब्रेक की जगह दबा दिया एक्सेलरेटर- कोलार थाना प्रभारी संजय सोनी के मुताबिक, चालक अत्यधिक नशे में था। उसने ब्रेक लगाने के बजाय गलती से एक्सेलरेटर दबा दिया, जिससे कार बेकाबू हो गई। हादसे के बाद इनोवा का स्पीडोमीटर 90 किमी/घंटे पर ही अटका मिला।

कई लोगों को चपेट में लिया- बेकाबू गाड़ी ने स्कूटी को टक्कर मारने से पहले सड़क पर कई अन्य लोगों को भी अपनी चपेट में ले लिया। टक्कर इतनी तेज थी कि स्कूटी के परखच्चे उड़ गए और पिता-पुत्र सड़क पर दूर जा गिरे।

परिचित की कार मांगकर लाया था- पुलिस के अनुसार, 21 वर्षीय आरोपी चालक अपनी किसी परिचित की कार मांगकर पार्टी में शामिल होने लाया था। कार के अंदर से एक खाली व एक भरी हुई शराब की बोतल, डिस्पोजल और कंडोम मिले हैं। टक्कर के तुरंत बाद इनोवा के एयरबैग खुल गए, जिससे आरोपी चालक बाल-बाल बच गया।

भीड़ ने चालक को पीटा, कार में की तोड़फोड़- हादसे के बाद मौके पर मौजूद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। भीड़ ने नशे में धुत चालक को मौके पर ही दबोच लिया और उसके साथ जमकर मारपीट कर दी। गुस्साए लोगों ने इनोवा कार में भी तोड़फोड़ की। सूचना मिलते ही कोलार थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी चालक को भीड़ से बचाकर हिरासत में ले लिया। गंभीर रूप से घायल शुभम अवस्थी को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पोस्टमॉर्टम के बाद शव परिजन को सौंपा जाएगा।

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के पावर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रेनिंग सेंटर की डिजिटल पहल, आधिकारिक वेबसाइट शुरू

प्रशिक्षण, छात्रावास एवं ई-लाइब्रेरी की सुविधाएं अब मिलेगी ऑनलाइन

भोपाल। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के पावर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रेनिंग सेंटर (PDTC) द्वारा अपनी आधिकारिक वेबसाइट विकसित कर सफलतापूर्वक प्रारंभ की गई है। वेबसाइट के माध्यम से पीडीटीसी की प्रशिक्षण गतिविधियों, उपलब्ध अधोसंरचना, छात्रावास सुविधाओं एवं संस्थान से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण जानकारियां अब ऑनलाइन उपलब्ध होंगी। पीडीटीसी के डायरेक्टर श्री सुधीर कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि वेबसाइट पर आयोजित होने वाले विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों की जानकारी भी उपलब्ध कराई गई है। इसके अलावा, विषय-विशेषज्ञ एवं इच्छुक संकाय सदस्य पीडीटीसी में फैकल्टी रजिस्ट्रेशन एवं एम्पैनलमेंट के लिए अपनी जानकारी ऑनलाइन प्रस्तुत कर सकेंगे। कंपनी के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सुविधा के लिए वेबसाइट पर ई-लाइब्रेरी की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। इसके माध्यम से उपयोगी अध्ययन सामग्री, प्रशिक्षण संबंधी संसाधनों एवं अन्य डिजिटल सामग्री का ऑनलाइन उपयोग किया जा सकेगा। वेबसाइट के प्रारंभ होने से पीडीटीसी की प्रशिक्षण एवं छात्रावास संबंधी सेवाएं अधिक सुगम, पारदर्शी एवं प्रभावी होंगी। प्रशिक्षणार्थियों, अधिकारियों, कर्मचारियों एवं विषय-विशेषज्ञों को आवश्यक जानकारी और सेवाएं एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आसानी से उपलब्ध हो सकेंगी। पीडीटीसी द्वारा प्रशिक्षण व्यवस्था को आधुनिक एवं डिजिटल बनाने की दिशा में वेबसाइट का शुभारंभ एक महत्वपूर्ण पहल है।

जुलाई माह में 'टाइम ऑफ डे' टैरिफ के तहत

9 लाख 26 हजार से अधिक स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को मिली 10.96 करोड़ रुपये की छूट

भोपाल/ग्वालियर। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के कार्यक्षेत्र के भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर एवं चंबल संभाग अंतर्गत आने वाले 16 जिलों के स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं के लिए जुलाई माह लाभदायक रहा। कंपनी द्वारा स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को टाइम ऑफ डे टैरिफ व्यवस्था के तहत सोलर आवर्स (सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक) में बिजली की खपत पर 20 प्रतिशत तक की विशेष छूट का लाभ दिया जा रहा है।

इसी के तहत जुलाई-2026 में कंपनी कार्यक्षेत्र के कुल 9 लाख 26 हजार 737 स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को उनके बिजली बिलों में कुल 10.96 करोड़ रुपये की टीओडी छूट का सीधा लाभ मिला। इनमें भोपाल रीजन के 7 लाख 59 हजार 792 उपभोक्ताओं को 8 करोड़ 39 लाख 90 हजार रुपये तथा ग्वालियर रीजन के 1 लाख 66 हजार 945 उपभोक्ताओं को 2 करोड़ 56 लाख 53 हजार रुपये की छूट प्रदान की गई। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध संचालक श्री ऋषि गर्ग ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे आधुनिक तकनीक का लाभ उठाते हुए अपने परिसरों में स्मार्ट मीटर लगवाएं। स्मार्ट मीटर न केवल ऊर्जा प्रबंधन को बेहतर बनाते हैं, बल्कि उपभोक्ताओं को अपनी बिजली खपत पर नियंत्रण रखने और आर्थिक बचत करने का अवसर भी प्रदान करते हैं। उन्होंने बताया कि टाइम ऑफ डे टैरिफ के तहत स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को सोलर आवर्स (सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक) बिजली उपयोग करने पर ऊर्जा प्रभार की सामान्य दर में 10 किलोवाट तक स्वीकृत लोड/अनुबंध मांग वाले उपभोक्ताओं को 20 प्रतिशत तक की छूट दी जा रही है। स्मार्ट मीटर से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए उपभोक्ता 1912 पर संपर्क कर सकते हैं अथवा श्री कैलाश कुमार चौधरी, प्रबंधक (स्मार्ट मीटरिंग सेल) से संपर्क कर सकते हैं।

गुना में पंचायत सचिव ने घर में फांसी लगाकर दी जान

सुसाइड नोट मिलने की बात सामने आई, पुलिस जांच में जुटी

गुना। शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में पंचायत सचिव मुकुट भार्गव (58) ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वह साई सिटी कॉलोनी में रहते थे और ख्यावदा पंचायत में पंचायत सचिव के पद पर कार्यरत थे। घटना के पीछे की वजह फिलहाल स्पष्ट नहीं हो सकी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जानकारी के अनुसार, मुकुट भार्गव मंगलवार शाम करीब 5 बजे तक संपर्क में थे। इसके बाद उनका मोबाइल फोन बंद हो गया। परिवार के लोग जब करीब 7 बजे घर पहुंचे तो दरवाजा अंदर से बंद मिला। काफी प्रयास के बाद भी दरवाजा नहीं खुलने पर परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और दरवाजा खुलवाकर अंदर प्रवेश किया। घर के भीतर मुकुट भार्गव फंदे पर लटके मिले। पुलिसकर्मियों ने उन्हें नीचे उतारा और तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया।

पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा- बुधवार सुबह जिला अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम कराया गया। आवश्यक कार्रवाई के बाद पुलिस ने शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस ने मामले में मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल आत्महत्या के कारणों को लेकर पुलिस की ओर से कोई स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है।

सूत्रों के हवाले से यह जानकारी सामने आई है कि मुकुट भार्गव ने एक सुसाइड नोट छोड़ा है, जिसमें कुछ लोगों के नाम लिखे होने की बात कही जा रही है। हालांकि पुलिस की जांच पूरी होने और नोट की पुष्टि होने से पहले इसके आधार पर किसी व्यक्ति की भूमिका को लेकर निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा। पुलिस सुसाइड नोट सहित अन्य तथ्यों की जांच कर रही है। पुलिस अब मृतक के परिवार, परिचितों और कार्यस्थल से जुड़े लोगों से जानकारी जुटा रही है। साथ ही मोबाइल फोन और सामने आए अन्य साक्ष्यों की भी जांच की जा रही है, ताकि घटना की वास्तविक वजह सामने आ सके।

मुरैना में अवैध रेत खनन पर पुलिस की सख्ती

पुलिस अधीक्षक धर्मराज मीना ने आधी रात चार चौकिया का निरीक्षण कर दिए दिशा निर्देश

मुरैना। चंबल नदी से होने वाले अवैध रेत उत्खनन, परिवहन और भंडारण पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस ने निगरानी व्यवस्था और कड़ी कर दी है। खासतौर पर रात के समय रेत से जुड़े वाहनों की आवाजाही पर नजर रखने के लिए जिले में चेकिंग और गश्त बढ़ाई गई है। पुलिस अधिकारियों को संदिग्ध वाहनों की जांच करने और अवैध गतिविधि सामने आने पर संबंधित विभागों के साथ समन्वय कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।

पुलिस अधीक्षक धर्मराज मीना ने देर रात जिले में बनाए गए विभिन्न स्थायी और अस्थायी चेकिंग प्वाइंट का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पुलिसकर्मियों की ड्यूटी व्यवस्था, वाहनों की जांच, निगरानी के इंतजाम और नाकों पर तैनात बल की स्थिति की जानकारी ली। एसपी ने अधिकारियों को रात के समय विशेष सतर्कता बरतने तथा चेकिंग में किसी तरह की लापरवाही नहीं करने के निर्देश दिए।

एसपी ने पुलिसकर्मियों को चंबल नदी के घाटों से निकलने वाले रेत परिवहन के संभावित मार्गों पर लगातार निगरानी रखने को कहा। उन्होंने संदिग्ध वाहनों को रोककर उनकी बारीकी से जांच करने तथा आवश्यक दस्तावेजों का परीक्षण करने के निर्देश दिए। अवैध रेत परिवहन की शिकायत मिलने पर संबंधित विभागों के साथ समन्वय कर नियमानुसार कार्रवाई करने को भी कहा गया है।

पुलिस की ओर से संवेदनशील क्षेत्रों और रेत परिवहन वाले मार्गों पर नियमित पेट्रोलिंग बढ़ाने की व्यवस्था की जा रही है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि अलग-अलग समय पर अचानक चेकिंग की जाए, ताकि अवैध खनन और परिवहन में शामिल लोगों को कार्रवाई से बचने का मौका न मिले।

रात में निरीक्षण के दौरान एसपी धर्मराज मीना ने मुगपुरा, महचंदपुर चौराहा, मैयाना और सराय क्षेत्र के गार्ड प्वाइंट सहित अन्य स्थानों का जायजा लिया। उन्होंने मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों से चेकिंग व्यवस्था की जानकारी ली और रात में की जा रही निगरानी की स्थिति देखी।

हेमंत खण्डेलवाल ने भोपाल में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स से किया संवाद

विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में सोशल मीडिया की भूमिका महत्वपूर्ण

भोपाल। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व विधायक श्री हेमंत खण्डेलवाल ने बुधवार को भोपाल में ''सोशल मीडिया डायलॉग कॉफी विथ स्टेट प्रेसिटेंड'' कार्यक्रम में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स से संवाद करते हुए कहा कि विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में सोशल मीडिया की भूमिका महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का जो लक्ष्य निर्धारित किया है, वह केवल सरकार का लक्ष्य नहीं, बल्कि 140 करोड़ देशवासियों का सामूहिक संकल्प है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए समाज के हर वर्ग, हर युवा और हर नागरिक की सहभागिता आवश्यक है। सोशल मीडिया लोगों की राय बनाने और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। सोशल मीडिया अब केवल मनोरंजन या सूचना के

आदान-प्रदान का माध्यम नहीं रह गया है, बल्कि यह समाज के विचार, व्यवहार और दिशा को प्रभावित करने वाला एक सशक्त माध्यम बन चुका है। युवा सोशल मीडिया को राष्ट्र निर्माण का माध्यम बनाएं। ऐसे में आप सभी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की भूमिका समाज निर्माण में अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है।

विकसित भारत के संकल्प को जन-जन तक पहुंचाने में सोशल मीडिया का उपयोग हो

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष श्री हेमंत खण्डेलवाल ने कहा कि विकसित भारत के संकल्प को जन-जन तक पहुंचाने और इसे जनभागीदारी का व्यापक आंदोलन बनाने में सोशल मीडिया की भूमिका अत्यंत प्रभावशाली है। आप सभी युवा सोशल मीडिया का उपयोग विकसित भारत के संकल्प को जन-जन तक पहुंचाने में करें। आज एक पोस्ट, एक वीडियो, एक रील या एक सकारात्मक विचार कुछ ही समय में लाखों लोगों तक पहुंच सकता है। इसलिए सोशल मीडिया के जरिए आप सभी लोगों की जितनी पहुंच है, देश को विकसित बनाने में आपकी भागीदारी भी उतनी ही बड़ी हो जाती है। उन्होंने कहा कि हम सभी का प्रयास होना चाहिए कि सोशल मीडिया के माध्यम से सकारात्मकता, राष्ट्र निर्माण, नवाचार, युवा शक्ति, आत्मनिर्भरता और विकास की सोच को आगे बढ़ाया जाए। देश की उपलब्धियों, युवाओं की सफलता, स्टार्ट-अप, तकनीक, शिक्षा, रोजगार, महिला सशक्तिकरण और जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाई जाए।

युवाओं की सोशल मीडिया में हर पोस्ट-संदेश में देश के उज्ज्वल भविष्य की झलक दिखनी चाहिए

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष श्री हेमंत खण्डेलवाल ने कहा कि हमें सोशल मीडिया को समाज को जागरूक करने, जोड़ने और राष्ट्र निर्माण में सहभागी बनाने का माध्यम बनाना है। हमारी हर पोस्ट और हर संदेश में भारत के उज्ज्वल भविष्य की झलक दिखाई देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 का विकसित भारत तभी संभव होगा, जब प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व वाली मध्यप्रदेश की भाजपा सरकार के प्रयासों के साथ समाज की सक्रिय भागीदारी भी सुनिश्चित होगी। इस महान संकल्प को जनआंदोलन बनाने में आप सभी की भूमिका महत्वपूर्ण है। उन्होंने युवाओं और इन्फ्लुएंसर्स से कहा कि हम मिलकर सोशल मीडिया की शक्ति को सकारात्मक दिशा दें और विकसित, आत्मनिर्भर एवं सशक्त भारत के निर्माण में अपना योगदान सुनिश्चित करें।

इस अवसर पर सोशल मीडिया के प्रदेश संयोजक श्री सुयश त्यागी, सोशल मीडिया के चंबल संभाग प्रभारी श्री आयुष शर्मा एवं सोशल मीडिया के पदाधिकारी उपस्थित रहे।

संक्षिप्त समाचार

बांसवाड़ा की सड़क बनाने बिना सूचना तोड़ी खेतों की जाली, फिर आगे नहीं किया कार्य

राजगढ। वार्ड 08 के बांसवाड़ा क्षेत्र को छार बाग होते हुए शहर के मुख्य क्षेत्र किले से जोड़ने वाली सड़क पिछले एक साल से परेशानी का सबब बनी हुई है। बीते साल 2025 की बारिश में दीवार क्षतिग्रस्त होने के बाद बंद हुई सड़क को अब तक पूरी तरह व्यवस्थित नहीं किया जा सका है। नगरपालिका ने दीवार का निर्माण तो करा दिया, लेकिन उससे जुड़ी सड़क का काम अधूरा छोड़ दिया। तीन महीने से सड़क खुदी पड़ी है और बारिश के बाद यहां कीचड़ फैलने से रहवासियों का निकलना मुश्किल हो गया है। दरअसल, पिछले साल मई में सड़क किनारे बनी दीवार क्षतिग्रस्त होने के बाद करीब छह महीने तक रास्ता संकरा पड़ा रहा। रहवासियों की लगातार मांग, विपक्ष के प्रदर्शन और शिकायतों के बाद नगरपालिका ने पिछले साल के अंत में करीब 50 लाख रुपए की लागत से दीवार और मुक्तिधाम चौराहे तक सड़क निर्माण का टेंडर किया। इसके करीब दो महीने बाद ठेकेदार ने दीवार का काम तो कर दिया, लेकिन सड़क का काम अधूरा छोड़ दिया। काम पूरा करवाएंगे। ट्बांसवाड़ा की सड़क का बचा काम पूरा कराने के लिए संबंधित ठेकेदार को नोटिस जारी किया था। अब इसकी स्थिति की जानकारी लेता हूं। शीघ्र काम पूरा करवाएंगे।' नुकसान के बाद काम बंद सड़क चौड़ी करने के लिए मई में ठेकेदार ने सड़क किनारे स्थित निजी जमीन के खेत और फलोद्यान की जाली भी बिना सूचना तोड़ दी। यहां दो लोगों के खेत हैं, जिनमें फसल के साथ फलदार पौधे लगे हैं। खेत मालिक निरंजन लाल बाथम ने नुकसान की भरपाई की मांग को लेकर प्रशासन को आवेदन दिया है। जाली तोड़ने के बाद एक दिन काम चला और फिर बंद हो गया। ढाई महीने से अधिक समय बीतने के बावजूद दोबारा काम शुरू नहीं हुआ। जाली टूटने से खेत मालिक इस बार बोवनी भी नहीं कर पाए।

अजाक्स ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

राजगढ़। संगठन का आरोप है कि शिक्षक संयुक्त मोर्चा के ज्ञापन के दौरान तत्कालीन एसडीएम निधि भारद्वाज ने अजाक्स, भीम आर्मी और जयस जैसे संगठनों को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की। संगठन ने घटना के प्रत्यक्षदर्शियों के बयान दर्ज कराने तथा सीसीटीवी फुटेज और उपलब्ध ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग की जांच कराने की मांग की। साथ ही कथित टिप्पणी प्रमाणित होने पर संबंधित नियमों के तहत कार्रवाई और संगठन के संबंध में आपत्तिजनक शब्द वापस लेने की मांग की। अजाक्स ने पदाधिकारियों के खिलाफ प्रतिशोधात्मक कार्रवाई नहीं करने का भी आग्रह किया। ज्ञापन सौंपने के दौरान जिलाध्यक्ष जगदीश वर्मा, कार्यकारी अध्यक्ष नरेन्द्र जाधव, पवित्रा वर्मा, दिनेश जोनवाल, जुगराज वर्मा, रोडीलाल वर्मा, गोकुल प्रसाद सिंहवाल आदि मौजूद थे।

खोयरी मंदिर पर आयोजित हुआ 27 वां कालसर्प दोष निवारण अनुष्ठान

राजगढ़। नागपंचमी और सावन सोमवार के विशेष संयोग पर शहर के शिवालय खोयरी मंदिर पर विशेष कालसर्प दोष निवारण अनुष्ठान का आयोजन हुआ। अनुष्ठान आयोजनकर्ता ज्योतिषाचार्य पं हेमेंद्र शर्मा ने बताया कि इस बार राजगढ़ में आयोजित यह 27 शिवालय अनुष्ठान था। जिसमें इस बार राजगढ़ नगर और जिले सहित भोपाल, सागर, जबलपुर, इकलेरा और भावनगर गुजराज के लोग शामिल हुए। करीब 40 लोगो ने इस विशेष अनुष्ठान में शामिल हुए। वैदिक मंत्रोच्चार और विशेष पूजन पद्वति से अनुष्ठान से संपन्न करवाया गया। सुबह करीब 10 बजे से प्रारंभ हुआ अनुष्ठान दोपहर बाद संपन्न हुआ। इधर...बाबा बैजनाथ को लगाए छप्पन भोग सावन के तीसरे सोमवार के अवसर पर खोयरी मंदिर में सुबह से श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी, सुबह करीब 6 बजे से दोपहर तक हजारों श्रद्धालुओं ने बाबा बैजनाथ के दर्शन कर जलाभिषेक किया। दोपहर बाद बाबा भोलेनाथ का श्रृंगार कर 56 भोग अर्पित किए गए। श्रद्धालुओं के सहयोग से यह आयोजन संपन्न हुआ।

सोयाबीन पर इल्लियों और बांझपन की दोहरी मार, किसानों ने सौंपा ज्ञापन

झाड़ला। क्षेत्र में सोयाबीन की फसल पर इल्लियों के बढ़ते प्रकोप और बांझपन की शिकायत से किसान परेशान हैं। कई गांवों में इल्लियों के कारण फसल को नुकसान पहुंचा है, वहीं कुछ खेतों में बांझपन की शिकायत भी सामने आई है। फसल खराब होने की स्थिति को देखते हुए किसानों ने शासन से राहत और मुआवजे की मांग की है। इसी मांग को लेकर किसानों ने एसडीएम नरसिंहगढ़ के नाम तहसीलदार अनाग्रिका कंजोनिया वर्मा को ज्ञापन सौंपा। किसानों ने बताया कि सोयाबीन में इल्लियों का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। कई खेतों में फसल प्रभावित होकर खराब होने की स्थिति में पहुंच गई है। इसके साथ ही सोयाबीन में बांझपन की समस्या भी सामने आ रही है, जिससे उत्पादन प्रभावित होने की आशंका है। किसानों ने कहा कि फसल में हुए नुकसान का आकलन कर शासन स्तर से नियमानुसार राहत और मुआवजा दिया जाए, ताकि खराब फसल से होने वाले आर्थिक नुकसान की भरपाई हो सके। टीम भेजकर नुकसान का आकलन कराने की मांग ज्ञापन में किसानों ने प्रभावित गांवों और खेतों में कृषि विभाग की टीम भेजकर फसल की स्थिति का आकलन कराने की मांग की है, ताकि नुकसान की वास्तविक स्थिति सामने आ सके। किसानों का कहना है कि समय पर आकलन होने से प्रभावित किसानों को नियमानुसार राहत और मुआवजा मिल सकेगा। उन्होंने प्रशासन से मामले को गंभीरता से लेते हुए जल्द कार्रवाई करने की मांग की।

राजगढ़ हत्याकाण्ड में नया मोड़ ASI के समर्थन में आए पूर्व सैनिक, कलेक्टर को ज्ञापन सौंप निष्पक्ष जांच और न्याय की मांग की

राजगढ। राजगढ़ जिले के इकलेरा गांव में जमीन विवाद के दौरान गोली लगने से दीपक मोवे की मौत के मामले में नया मोड़ आ गया है। पूर्व सैनिक संगठन ने सहायक उपनिरीक्षक (स्‍ढ़) दिलीप कुंभकार के समर्थन में कलेक्टर डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा को ज्ञापन सौंपकर मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है।

पूर्व सैनिक संगठन के जिलाध्यक्ष हिन्दू सिंह दांगी के नेतृत्व में जिलेभर से पूर्व सैनिक कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। उन्होंने दावा किया कि घटना के समय दिलीप कुंभकार अपने प्लॉट पर मौजूद थे और कुछ लोगों ने उन पर हथियारों से हमला किया था। संगठन के मुताबिक, घिर जाने के बाद कुंभकार ने अपनी जान बचाने के लिए लाइसेंसी बंदूक से फायर किया।

आत्मरक्षा में फायरिंग का दावा

संगठन ने ज्ञापन में बताया कि 16 अगस्त को दोपहर करीब 12 बजे दिलीप कुंभकार अपने प्लॉट पर निर्माण कार्य करा रहे थे। इसी दौरान दीपक मोवे, मुकेश जाटव, संतोष कुमार जाटव सहित अन्य लोग वहां पहुंचे। संगठन का दावा है कि उनके पास कुल्हाड़ी, फरसा, चाकू और लाठी जैसे हथियार थे। पूर्व सैनिकों के अनुसार, कुंभकार को चारों तरफ से घेरकर हमला किया गया। ऐसे में उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए लाइसेंसी बंदूक से फायर किया। इसी दौरान गोली लगने से दीपक मोवे की मौत हो गई।

कलेक्टर ने पूछा- बचाव में गोली चलाता है क्या : पूर्व सैनिकों ने कलेक्टर को घटना की जानकारी देते हुए कहा कि कुंभकार पर हमला हुआ था और उन्हें अपनी जान का खतरा था। इस पर कलेक्टर ने सवाल किया कि बचाव में कोई गोली चलाता है क्या? सैनिकों ने दोबारा घटना के दौरान हमला होने और जान का खतरा होने की बात रखी। संगठन ने पुलिस पर एकतरफा कार्रवाई करने का आरोप भी लगाया। उनका कहना है कि कुंभकार की शिकायत दर्ज नहीं की गई और दूसरे पक्ष की शिकायत पर उनके खिलाफ कार्रवाई की गई।

परिवार पर कार्रवाई का भी आरोप : पूर्व सैनिकों ने आरोप लगाया कि घटना के बाद पुलिस प्रशासन दबाव में कुंभकार के घर पहुंचा और मकान तोड़ने की बात कही। इस पर कलेक्टर ने कहा कि यदि अतिक्रमण होगा तो कार्रवाई की जाएगी। हालांकि उन्होंने पूर्व सैनिकों से यह भी कहा कि वे मामले को दिखवा लेंगे। ज्ञापन में कुंभकार के बेटे अभिषेक, भाई सुरेश और भतीजे सचिन को पुलिस द्वारा ले जाने का भी उल्लेख किया गया है।

17 साल सेना में सेवा के बाद पुलिस में ASI : पूर्व सैनिक संगठन के अनुसार, दिलीप कुंभकार ने भारतीय सेना में करीब 17 वर्ष तक सेवा की है। इसके बाद वे जिला पुलिस बल शाजापुर में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ हुए। संगठन का कहना है कि इकलेरा में उनके प्लॉट को लेकर पहले से विवाद चल रहा था। प्लॉट के दस्तावेज होने के बावजूद दूसरे पक्ष द्वारा कब्जे का दावा किया गया था और मामला न्यायालय तक भी पहुंचा था।

निष्पक्ष जांच की मांग : पूर्व सैनिक संगठन ने कलेक्टर से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने, दिलीप कुंभकार और उनके परिवार को न्याय दिलाने तथा मामले में दोषी पाए जाने वाले लोगों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं, गोलीकांड में दीपक मोवे की मौत को लेकर पुलिस की जांच जारी है।

काशी विश्वनाथ मंदिर में पहुंच रहे श्रद्धालु

राजगढ। कस्बे के काशी विश्वनाथ महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। मेन रोड स्थित मंदिर में सुबह 5 बजे से ही दर्शन के लिए लंबी कतारें लगना शुरू हो जाती हैं। सब्जी बाजार स्थित महादेव मंदिर में महिलाएं भजन-कीर्तन कर रही हैं। श्रद्धालु भगवान शिव का जलाभिषेक और पूजन-अर्चन कर बेलपत्र अर्पित करते हुए परिवार की सुख-समृद्धि की कामना कर रहे हैं। मंदिर समिति के अनुसार प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी बाबा भोलेनाथ की शाही सवारी धूमधाम से निकाली जाएगी।

सवा लाख पार्थिव शिवलिंग निर्माण का महाआरती के साथ हुआ समापन

राजगढ़। इंगले कॉलोनी स्थित आशीर्वाद हनुमान मंदिर में सावन माह के अवसर पर आयोजित तीन दिवसीय सवा लाख पार्थिव शिवलिंग निर्माण एवं विशेष पूजा-अर्चना का सोमवार को महाआरती के साथ समापन हुआ। मंदिर समिति के तत्वावधान में लगातार 14 वर्ष आयोजित कार्यक्रम में 16 से 18 अगस्त तक श्रद्धालुओं ने भक्तिभाव से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर भगवान शिव का पूजन व जलाभिषेक किया। पं. दीपक जोशी ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ विशेष पूजा-अर्चना एवं अभिषेक कराया। आयोजन में बड़ी संख्या में महिलाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। तीनों दिन मंदिर परिसर भक्तिमय वातावरण से सराबोर रहा। समिति अध्यक्ष मोतीलाल कुंभकार, सुरेश प्रजापति, आत्माराम गोड़, रामप्रसाद दांगी सहित पदाधिकारी व बड़ी संख्या में मातृशक्ति मौजूद रही।

नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 23 साल की सजाःमाइनर को गुजरात ले गया,8 महीने तक रेप किया, कोर्ट ने 5 हजार का जुर्माना भी लगाया

राजगढ़। राजगढ़ की जिला अदालत ने मंगलवार को नाबालिग से दुष्कर्म और उसे बंधक बनाकर रखने के दोषी दिनेश सिसोदिया (42) को 23 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उस पर 5 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट उपेंद्र प्रताप सिंह ने यह फैसला सुनाया। मामला 20 फरवरी 2020 का है। नाबालिग की मां ने नरसिंहगढ़ थाने में उसके लापता होने की शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस करीब 8 महीने तक उसकी तलाश करती रही। अक्टूबर 2020 में नाबालिग ने किसी के फोन से पिता को कॉल किया। उसने बताया कि वह गुजरात के नैनपुर गांव में है। दिनेश उसे वहां रखे हुए है।

कई महीने तक गुजरात में करता रहा रेप : फिर पुलिस ने 14 अक्टूबर को नाबालिग को वहां से बरामद किया। जांच में पता चला कि नाबालिग को पहले उसका पड़ोसी रवि अपने साथ ले गया था। बाद में रवि उसे दिनेश के पास छोड़कर चला गया।

इसके बाद दिनेश नाबालिग को गुजरात ले गया। वहां उसे कई महीने तक कमरे में रखा। उसके साथ दुष्कर्म किया। विरोध करने पर मारपीट और धमकी दी। मामले में दिनेश के खिलाफ दुष्कर्म, मारपीट और पॉक्सो समेत धाराओं में केस दर्ज हुआ। फिर कोर्ट ने दिनेश को दोषी मानते हुए कुल 23 साल की सजा सुनाई।

फरार आरोपी के खिलाफ भी चलेगा ट्रायल : मामले में नाबालिग को पहले अपने साथ ले जाने वाला रवि फरार है। उसके खिलाफ अब उसकी गैरमौजूदगी में ट्रायल चलाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

सभी स्कूलों में बिजली, पानी की व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जायें-डीएम

श्योपुर , निप्र। कलेक्टर सुश्री शीला दाहिमा ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित समय सीमा की बैठक के दौरान निर्देश दिये कि सभी स्कूलों में बिजली और पानी की सुविधाएं सुनिश्चित की जायें। उन्होंने कहा कि विद्यालयों का निरीक्षण करायें तथा ऐसे विद्यालय जिनमें अभी भी बिजली और पानी की व्यवस्थाएं नही हैं, वहां पर यह सुविधाएं सुनिश्चित की जायें। उन्होंने सभी बालिका शौचालयों को फंक्शनल बनाये रखने के निर्देश देते हुए कहा कि सभी विद्यालयों में बालिका शौचालयों की सुविधा सुनिश्चित की जायें। इसके साथ ही उन्होंने स्कूल भवनो की रिपोर्ट प्रस्तुत नही करने पर डीपीसी श्री भूपेन्द्र शर्मा को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश भी दिये। उन्होंने कहा कि जून माह में ही सभी विद्यालयों के भवनों का भौतिक सत्यापन कराये जाने हेतु निर्देश दिये गये थे, जिसके संबंध में रिपोर्ट अभी तक अप्राप्त है। इसके साथ ही टीबी रोगियों को मानक अनुसार फूड बॉस्केट वितरण नही किये जाने पर क्षय रोग अधिकारी डॉ यतेन्द्र रावत एवं कृषको की ग्रामवार जानकारी उपलब्ध नही कराने पर उप संचालक कृषि श्री जीके पचौरिया को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिये गये। कलेक्टरसमरसता संकल्प अभियान के तहत 20 अगस्त से 10 सितंबर तक आयोजित होने वाली कलश रथ यात्रा आयोजन की सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाये।

श्रमिक नियोजन बढ़ाकर विकास कार्यों को दें गति, लापरवाही पर होगी कार्रवाई - कलेक्टर

मुरैना , निप्र। विकसित भारत-रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) ''वीबी-जी-राम'' के अंतर्गत जिले में ग्रामीण श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने के साथ-साथ विकास कार्यों को गति प्रदान की जा रही है। जिले की 478 ग्राम पंचायतों में से 314 ग्राम पंचायतों में विभिन्न रोजगारपरक एवं विकास कार्य प्रगतिरत हैं। कलेक्टर श्री लोकेश कुमार जांगिड़ ने श्रमिक नियोजन बढ़ाने के निर्देश देते हुए कहा कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में न्यूनतम 10 श्रमिकों का नियोजन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने यह निर्देश सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा बैठक में दिए। श्री उमेश अवस्थी, विभिन्न जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालनसहायक यंत्री तथा संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने विभिन्न विकासखंडों में श्रमिक नियोजन एवं रोजगारपरक कार्यों की प्रगति की समीक्षा की।

सुठालिया परियोजना के किसानों का प्रदर्शन:4 गुना मुआवजे की मांग, बांध पर आंदोलन की चेतावनी, जिला कांग्रेस अध्यक्ष बोले- सरकार की नाकामी

राजगढ़ । राजगढ़ में सुठालिया सिंचाई परियोजना से प्रभावित किसानों ने मंगलवार को मुआवजे और पुनर्वास की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट के बाहर धरना दिया। गुना और राजगढ़ जिले के किसान कलेक्टर कार्यालय पहुंचे थे। किसानों की मुख्य मांग है कि परियोजना से प्रभावित सभी परिवारों को चार गुना मुआवजा दिया जाए। साथ ही वर्षों से लंबित पुनर्वास और परिसंपत्तियों के भुगतान का निपटारा किया जाए।

धरने के दौरान नेताओं ने सरकार पर दबाव बनाने के लिए आंदोलन को बांध स्थल तक ले जाने का संकेत दिया। उन्होंने कहा कि मांगें नहीं मानी गईं तो परियोजना का काम रोका जा सकता है। जिला पंचायत अध्यक्ष बोले- अब केवल ज्ञापन देने से काम नहीं चलेगा जिला पंचायत अध्यक्ष चंदरसिंह सौंधिया ने किसानों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि अब केवल ज्ञापन देने से काम नहीं चलेगा। उन्होंने प्रभावित 65 गांवों के किसानों से एकजुट होकर बांध स्थल पर काम रोकने का अभियान चलाने का आह्वान किया। सौंधिया ने कहा कि जब परियोजना का काम रुकेगा, तभी सरकार और जनप्रतिनिधियों का ध्यान किसानों की मांगों पर जाएगा। उन्होंने कहा कि चार गुना मुआवजे के लिए लंबी प्रक्रिया की जरूरत नहीं है। सरकार कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव पास कर सभी प्रभावित किसानों को चार गुना मुआवजा देने का फैसला कर सकती है। उन्होंने कहा कि जब तक किसानों के खातों में पूरा मुआवजा नहीं पहुंचता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। प्रियव्रत बोले-

किसानों का धरना देना दर्शाता है सरकारी नाकामी पूर्व मंत्री और जिला कांग्रेस अध्यक्ष प्रियव्रत सिंह ने कहा कि किसानों को अपने अधिकार के लिए कलेक्ट्रेट के बाहर बैठना पड़ रहा है। इससे बड़ी प्रशासनिक और सरकारी नाकामी क्या होगी। उन्होंने कहा कि गुना और राजगढ़ के प्रभावित किसान लंबे समय से मुआवजे और पुनर्वास लाभ की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनकी समस्या का स्थायी समाधान नहीं हुआ। 80% किसानों को कम दर पर भुगतान का दावा किसानों का कहना है कि परियोजना में करीब 80 प्रतिशत प्रभावित किसानों को पहले कम दर से भुगतान किया जा चुका है। करीब 20 प्रतिशत किसानों का भुगतान अभी बाकी है। किसानों की मांग है कि जिन किसानों को कम दर पर राशि मिल चुकी है, उन्हें संशोधित दर के अनुसार अंतर की राशि दी जाए। वहीं, बाकी किसानों को चार गुना मुआवजा दिया जाए। मकान, कुएं और पेड़ों का मुआवजा भी लंबित किसानों ने बताया कि जमीन के अलावा मकान, कुएं, ट्यूबवेल, फलदार पेड़, सिंचाई पाइपलाइन और अन्य परिसंपत्तियों का मुआवजा भी कई मामलों में लंबित है। टोड़ी, निवारा और गुर्जरखेड़ी के प्रभावित परिवारों के मकान का मुआवजा देने की मांग की गई। किसानों ने टोड़ी के 24 और गुर्जरखेड़ी के तीन मकानों को पूर्ण प्रभावित मानकर दोबारा परीक्षण कराने की मांग भी रखी। पहले धरना, फिर मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन किसानों ने पहले कलेक्टर कार्यालय के बाहर धरना दिया। इसके बाद जिला पंचायत अध्यक्ष चंदरसिंह सौंधिया और पूर्व मंत्री प्रियव्रत सिंह ने किसानों को संबोधित किया। नेताओं के संबोधन के बाद किसानों ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में परिवार आईडी, विस्थापन लाभ, भूमिहीन और 90 से 100 प्रतिशत प्रभावित परिवारों को पात्रता के अनुसार लाभ देने की मांग की गई। किसानों ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने जल्द निर्णय नहीं लिया तो आंदोलन को बांध स्थल तक ले जाकर अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया जाएगा।

गोविंद सिंह राजपूत ने प्रदेश कार्यालय में कार्यकर्ताओं की सुनी जनसमस्याएं

जनसमस्याओं के त्वरित निराकरण के दिए निर्देश

भोपाल। मध्यप्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत ने बुधवार को भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए पार्टी कार्यकर्ताओं से आत्मीय मुलाकात कर उनकी जनसमस्याओं को सुना। उन्होंने कार्यकर्ताओं की जनसमस्याओं का संबंधित अधिकारियों से तत्काल चर्चा कर समाधान कराया। जिन प्रकरणों में विस्तृत प्रक्रिया अपेक्षित है, उन्हें संबंधित विभागों को शीघ्र निराकरण के लिए भेजा गया। इस दौरान पार्टी के प्रदेश मंत्री श्री राजेन्द्र सिंह राजपूत उपस्थित रहे।

मध्यप्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत ने कार्यकर्ताओं को आश्वस्त किया कि उनकी ओर से प्राप्त जनसमस्याओं का गंभीरतापूर्वक परीक्षण कर प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र समाधान सुनिश्चित किया जाएगा। कार्यकर्ताओं के माध्यम से प्राप्त जनसमस्याओं का त्वरित, पारदर्शी और प्रभावी समाधान भाजपा सरकार एवं संगठन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

प्रयोगशाला से निर्माण स्थल तक पहुंचे नवाचार : मंत्री श्री सिंह

सुरक्षित, टिकाऊ और गुणवत्तापूर्ण अधोसंरचना का निर्माण हमारी प्राथमिकता

भोपाल (नप्र)। लोक निर्माण मंत्री श्री राकेश सिंह ने कहा कि नवाचार तभी सार्थक है, जब वह प्रयोगशाला से निकलकर वास्तविक निर्माण स्थल तक पहुंचे और मैदानी स्तर पर प्रमाणित परिणाम दे। नवीन तकनीकों को पहले पायलट परियोजनाओं एवं परीक्षण खंडों में परखा जाए तथा सफल परिणाम मिलने के बाद उन्हें व्यापक स्तर पर अपनाया जाए। वैज्ञानिक अनुसंधान केवल दस्तावेजों तक सीमित न रहे, बल्कि उसका सीधा लाभ अधोसंरचना परियोजनाओं और आमजन तक पहुंचे।

मंत्री श्री सिंह बुधवार को सीएसआईआर-केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली की प्लेटिनम जुबली के अवसर पर सीएसआईआर-एएमपीआरआई, भोपाल में आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। कार्यशाला का विषय सतत अधोसंरचना के लिए नवोन्मेषी सामग्री एवं उन्नत कंपोजिट था। इसका संयुक्त आयोजन सीएसआईआर-सीआरआरआई, नई दिल्ली और सीएसआईआर-एएमपीआरआई, भोपाल द्वारा किया गया।

मंत्री श्री सिंह ने सड़क एवं परिवहन अधोसंरचना के क्षेत्र में 75 वर्षों की उत्कृष्ट सेवाओं के लिए सीएसआईआर-सीआरआरआई को बधाई देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश के अधोसंरचना क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन आया है।

प्रधानमंत्री का विजन है कि अधोसंरचना का विकास तेज गति से हो, लेकिन निर्माण टिकाऊ, गुणवत्तापूर्ण, सुरक्षित और दीर्घकालिक भी हो। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में मध्यप्रदेश भी नवीन तकनीकों एवं नवाचारों को अपनाते हुए तेजी से आगे बढ़ रहा है।

मंत्री श्री सिंह ने कहा कि बढ़ते यातायात, भारी वाहनों, सीमित प्राकृतिक संसाधनों और बदलती जलवायु के बीच हमारा लक्ष्य केवल अधिक सड़कें बनाना नहीं, बल्कि सुरक्षित, टिकाऊ और पर्यावरण-अनुकूल अधोसंरचना विकसित करना होना चाहिए। इसके लिए वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को स्थानीय संसाधनों पर आधारित कम लागत वाली स्वदेशी तकनीकें विकसित करनी होंगी। नई तकनीकें गुणवत्तापूर्ण होने के साथ व्यावहारिक और किफायती भी होनी चाहिए। पराली सहित अनुपयोगी सामग्रियों का अधोसंरचना निर्माण में उपयोग कर पर्यावरणीय समस्याओं को उपयोगी संसाधनों में बदला जा सकता है।

मंत्री श्री सिंह ने कहा कि प्रयोगशालाओं में अच्छे परिणाम देने वाली तकनीकें कई बार अधिक लागत, सामग्री की अनुपलब्धता और व्यावहारिक कठिनाइयों के कारण निर्माण स्थल तक नहीं पहुंच पाती है। वैज्ञानिक संस्थानों, इंजीनियरों और निर्माण एजेंसियों को मिलकर इन बाधाओं का समाधान करना होगा। सीमित संसाधनों में अधिक मजबूत एवं लंबे समय तक चलने वाली सड़कें बनाना आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। उन्होंने रेलवे लाइनों के नीचे रेल परिचालन को न्यूनतम प्रभावित करते हुए अंडरपास निर्माण के लिए बॉक्स-जैकिंग तकनीक को प्रभावी समाधान बताया। इस तकनीक में प्रीकास्ट आरसीसी बॉक्स को नियंत्रित हाइड्रोलिक जैकिंग के माध्यम से रेलवे ट्रैक के नीचे स्थापित किया जाता है। इससे सीमित समय में सुरक्षित निर्माण के साथ रेल यातायात में व्यवधान भी न्यूनतम होता है। उन्होंने कहा कि लोक निर्माण विभाग केवल सड़क, भवन और पुलों का निर्माण नहीं करता, बल्कि इनके माध्यम से नागरिकों के जीवन को सरल, सुरक्षित एवं बेहतर बनाता है। इसी सोच के साथ विभाग ने लोक निर्माण से लोक कल्याण को अपना ध्येय वाक्य बनाया है।मंत्री श्री सिंह ने लोकपथ ऐप-2 की जानकारी देते हुए बताया कि नागरिक सड़क पर गड्ढे अथवा क्षति का जियो-टैग्ड फोटो ऐप पर अपलोड कर सकते हैं।

शहडोल में छात्राएं हॉस्टल से पैदल कलेक्टर से मिलने पहुंचीं

अधिकारी पीछे-पीछे दौड़े, बोलीं- खराब खाना दिया जा रहा, साफ-सफाई नहीं

शहडोल (नप्र)। शहडोल के कंचनपुर में स्थित आदिवासी कन्या हॉस्टल की 28 छात्राएं बुधवार सुबह व्यवस्थाओं से नाराज होकर पैदल कलेक्टर दफ्तर पहुंच गईं। छात्राओं ने कलेक्टर पार्थ जायसवाल से मिलकर हॉस्टल में साफ-सफाई और खाने की खराब क्वालिटी की शिकायत की। उनका कहना था कि बार-बार बोलने के बाद भी उनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

हॉस्टल अधीक्षिका ममता सिंह का कहना है कि छात्राएं मोबाइल चलाने, रील बनाने और जान-पहचान के लोगों की बर्थडे पार्टी में बाहर जाने की जिद कर रही थीं। मना करने पर वे नाराज होकर शिकायत करने चली गईं। अधीक्षिका ने बताया कि हॉस्टल में कुल 445 छात्राएं रहती हैं, जिनमें से केवल 28 छात्राएं ही दफ्तर पहुंची थीं। अगर व्यवस्था खराब होती, तो सभी शिकायत करने आतीं।

गार्ड को धक्का देकर निकलीं छात्राएं

छात्राओं के अचानक निकलने पर सुरक्षा गार्ड ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन आरोप है कि छात्राएं गार्ड को धक्का देकर बाहर निकल गईं। अधीक्षिका और अधिकारियों ने रास्ते में उन्हें समझाने का प्रयास किया, लेकिन वे अपनी बात कलेक्टर के सामने ही रखने पर अड़ी रहीं। जनजातीय विभाग के सहायक आयुक्त आनंद राय सिन्हा और अधीक्षिका ममता सिंह बच्चियों के पीछे चल रहीं थीं।

कलेक्टर ने बनाई जांच टीम

कलेक्टर पार्थ जायसवाल ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तुरंत जांच टीम बनाने का आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि जांच में जो भी बातें सामने आएँगी, उसी के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद छात्राओं को समझा-बुझाकर गाड़ी से वापस स्कूल भेज दिया गया। बताया जा रहा है कि यह पहली बार नहीं है जब छात्राएं छात्रावास से बाहर निकलकर अपनी समस्याएं लेकर कलेक्टर से मिलने पहुंची हैं। इस बार बड़ी संख्या में छात्राओं के एक साथ निकलने के कारण मामला अधिक गंभीर हो गया है। इस घटना ने छात्रावास की व्यवस्थाओं और छात्राओं की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं।

सड़कों पर सैलाब, नदियां उफान पर, डिंडौरी में नदी-नाले उफान पर, फिर बाढ़ के हालात, सतना में उफनी गुप्तगोदावरी

टूरिस्ट की एंट्री पर रोक, पन्ना में कई गांवों में घुसा पानी

भोपाल(नप्र)। मध्य प्रदेश में बारिश का दौर जारी है। कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। सतना के तराई क्षेत्र में मूसलाधार बारिश से चित्रकूट की गुप्तगोदावरी में पानी बढ़ गया है। पहाड़ी का पानी गुफाओं के ऊपर से बह रहा है। चित्रकूट नगर परिषद ने दोनों गुफाएं बंद कर पर्यटकों के प्रवेश पर रोक लगा दी है।

इसके साथ ही, सतना सिविल लाइन थाना क्षेत्र के भुमकहर गांव में 55 वर्षीय चरवाहा नाले में बह गया। सूचना मिलते ही सतना एसडीईआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। चरवाहे की तलाश जारी है। नाला संकरा होने और तेज पानी के बहाव के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन में परेशानी आ रही है। वहीं, डिंडौरी में बुधवार सुबह से भारी बारिश हो रही है। नदी-नाले उफान पर हैं। 12 से ज्यादा गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। पन्ना के बृजपुर क्षेत्र के कई गांव जलमग्न हैं। सिमरिया के बोदा गांव में भी पानी भर गया है। बारिश से खाने-पीने का सामान भी भीग गया है।

प्रदेश में अब तक 22.6 इंच बारिश हुई

मौसम केंद्र की माने तो प्रदेश में अब तक 573.1 मिमी यानी, 22.6 इंच बारिश हो चुकी है। हालांकि, यह अब तक की सामान्य बारिश 25.6 इंच (651.4 मिमी) की तुलना में 3 इंच कम है। वहीं, ओवरऑल 12 प्रतिशत कम पानी गिरा है। पूर्वी हिस्से में 16 प्रतिशत और पश्चिमी हिस्से में औसत से 9 प्रतिशत बारिश कम हुई है।

24 घंटे में 8 इंच तक हो सकती है बारिश

मौसम विभाग के मुताबिक, टीकमगढ़, पन्ना और नरसिंहपुर में अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में अगले 24 घंटे में 4 से 8 इंच तक बारिश हो सकती है। 18 अगस्त को झारखंड के ऊपर सक्रिय अवदाब के कारण पूर्वी मध्य प्रदेश में बारिश तेज हुई है।

मौसम विशेषज्ञ शैलेंद्र कुमार नायक ने बताया- 19 अगस्त को विंध्य, बुंदेलखंड और महाकौशल में भारी से अत्यधिक भारी बारिश का अलर्ट है। 20 से 24 अगस्त के बीच बारिश का असर धीरे-धीरे मध्य और पश्चिमी मध्य प्रदेश तक बढ़ सकता है। तेज बारिश जारी रही तो प्रदेश में सामान्य बारिश का कोटा पूरा हो सकता है। फिलहाल प्रदेश में सामान्य से 12त्न कम बारिश हुई है।

पानी से भरे गड्ढे में डूबे 3 बच्चे, मौत

इनमें दो सगे भाई, सीहोर में एलएंडटी कंपनी ने पाइप बिछाने की थी खुदाई

सीहोर (नप्र)। सीहोर में बारिश के पानी से भरे गड्ढे में डूबने से तीन बच्चों की मौत हो गई। इनमें दो सगे भाई थे। तीनों बच्चे खेलते-खेलते गड्ढे के पास पहुंचे। फिर नहाने के लिए उसमें उतर गए। स्थानीय लोगों ने शव तैरते देखे तो हादसे का पता चला। घटना इछावर में मोगरा रोड पर बुधवार दोपहर करीब एक बजे की है। मृतकों की पहचान 12 वर्षीय प्रशांत, 10 वर्षीय पृथ्वीराज और 11 वर्षीय दीक्षांत के रूप में हुई है। प्रशांत और पृथ्वीराज पिता सुभाल बागरी सगे भाई थे। दीक्षांत के पिता का नाम अखिलेश बागरी है। इलाके में ही रहने वाले जगदीश ने बताया कि जिस गड्ढे में बच्चे डूबे, वह एलएंडटी कंपनी ने पाइपलाइन बिछाने के लिए खोदा था।

पुलिस बोली- सभी पहलुओं की जांच कर रहे- एडिशनल एसपी प्रशांत चौबे ने कहा- हादसे में इछावर के वार्ड नंबर 12 के रहने वाले तीन बच्चों की मौत हुई है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शवों को निकालकर पोस्टमॉर्टम के लिए अस्पताल भेजा।

चौबे ने कहा- गड्ढे के निर्माण, उसकी स्थिति और संभावित लापरवाही समेत हादसे से जुड़े सभी पहलुओं की वैधानिक जांच की जा रही है।

ड्यूटी के दौरान एसएसबी जवान ने खुद को मारी गोली

भोपाल (नप्र)। भोपाल के कमला नगर थाना क्षेत्र स्थित सीएसडी कैंप डिपो में ड्यूटी के दौरान,एसएसबी के 35 वर्षीय जवान संदीप खरमटे ने सर्विस राइफल से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। जवान ने जबड़े के निचले हिस्से में राइफल सटाकर अंगूठे से ट्रिगर दबाया और गोली सिर से बाहर हो गई। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्ट्म के लिए हमीदिया अस्पताल भेज दिया। फिलहाल पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है।

सुबह 4 बजे पत्नी को मिली मौत की सूचना- मृतक की पत्नी के मुताबिक, बुधवार सुबह करीब 4 बजे विभाग की ओर से उन्हें पति की मौत की सूचना दी गई। संदीप से उनकी आखिरी बार मंगलवार रात करीब 10 बजे बातचीत हुई थी। उस समय संदीप ने बताया था कि वह ड्यूटी पर हैं। इसके बाद दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं हुई।

सुसाइड नोट का कराया जा रहा अनुवाद- पुलिस को संदीप के पास से मराठी भाषा में लिखा सुसाइड नोट मिला है। नोट को अनुवाद के लिए भेजा जा रहा है। कमला नगर थाना प्रभारी निरूपा पांडे के मुताबिक, नोट में अब तक जो बातें स्पष्ट हो सकी हैं, उनमें संदीप ने पत्नी से माफी मांगी है। साथ ही निजी कारणों से आत्महत्या करने की बात लिखी है।

परिजन के बयान और जांच के बाद स्थिति होगी स्पष्ट

पुलिस के मुताबिक, सुसाइड नोट का पूरा अनुवाद होने के बाद आत्महत्या की वजह स्पष्ट हो सकेगी। परिजनों के विस्तृत बयान अभी दर्ज नहीं किए जा सके हैं। पुलिस जवान के साथियों और विभागीय अधिकारियों से भी पूछताछ कर रही है। शव को हमीदिया अस्पताल की मॉर्च्युरी में सुरक्षित रखवाया गया है। घटनास्थल से मिले साक्ष्यों के आधार पर भी जांच की जा रही है।

टैक्सी हड़ताल जारी, बोर्ड ऑफिस चौराहे पर धरना, परिवहन मंत्री से मिलेंगे यूनियन पदाधिकारी

भोपाल (नप्र)। भोपाल में टैक्सी चालकों की हड़ताल जारी है। मंगलवार रात 12 बजे से टैक्सी संचालन बंद है। बुधवार को टैक्सी संगठन बोर्ड ऑफिस चौराहे पर धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके बाद यूनियन पदाधिकारी परिवहन मंत्री राव उदय प्रताप सिंह से मुलाकात करेंगे। बातचीत के बाद हड़ताल को लेकर आगे का फैसला होगा।

मंगलवार को परिवहन अधिकारियों और टैक्सी यूनियन के पदाधिकारियों के बीच हुई बैठक में फिलहाल कोई अंतिम फैसला नहीं हो सका था। बैठक में टैक्सी यूनियन कल्याण समिति संपूर्ण भारत के सचिव नफीस उद्दीन, भोपाल टैक्सी चालक संघ के महामंत्री राजेश कुमार नागले समेत अन्य पदाधिकारी शामिल रहे।

बोर्ड ऑफिस चौराहे पर धरना- टैक्सी संगठनों की ओर से बुधवार को बोर्ड ऑफिस चौराहे पर धरना-प्रदर्शन किया । टैक्सी चालक अपनी प्रमुख मांगों को लेकर सड़कों पर उतर आए हैं। संगठन की मांग है कि सरकार टैक्सियों के लिए उचित किराया तय करे, एग्रीगेटर कंपनियों की मनमानी पर रोक लगाए और प्राइवेट नंबर वाले वाहनों के व्यावसायिक इस्तेमाल पर कार्रवाई करे।

त्योहार से पहले मांगों को लेकर प्रदर्शन

टैक्सी ड्राइवरों का कहना है कि रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला है। ऐसे में वे टैक्सियां बंद कर अपनी मांगों के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। ड्राइवरों का कहना है कि टैक्सी बंद होने से त्योहार पर परिवार के लिए क्या लेकर जाएंगे और कमाई कैसे होगी। ड्राइवरों का कहना है कि एग्रीगेटर ऐप से मिलने वाले किराए से उनकी टैक्सी की किस्त तक नहीं निकल पा रही है। ऐसे में घर का खर्च चलाना मुश्किल हो रहा है।

लोग बोले- कैब हड़ताल का असर आम लोगों पर, ट्रेन पकड़ने में हुई देरी

भोपाल में एग्रीगेटर कंपनियों के खिलाफ टैक्सी चालक संघ की हड़ताल का असर अब आम लोगों पर दिखने लगा है। शहर के कई इलाकों में लोगों को कैब बुक करने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।कैब समय पर बुक नहीं होने से कई लोगों को ट्रेन पकड़ने में भी देरी हुई। यात्रियों का कहना है कि समय पर कैब नहीं मिलने के कारण स्टेशन पहुंचने में परेशानी हुई। वहीं, पूरी फैमिली के लिए एक ऑटो पर्याप्त नहीं था, इसलिए दूसरा ऑटो लेना पड़ा। इसके अलावा, ऑटो चालक इस स्थिति का फायदा उठाकर दोगुना किराया वसूल रहे हैं। एक स्थानीय ने कहा, जो दूरी पहले 40-50 रुपए में तय होती थी, अब उसके लिए ऑटो वाले 100 रुपए तक मांग रहे हैं। लोगों की मांग है कि प्रशासन जल्द इस विवाद को सुलझाए ताकि आम जनता को राहत मिल सके।

29 अगस्त को खेल प्रकोष्ठ आयोजित करेगा 'मुख्यमंत्री हॉकी कप' एवं खिलाड़ी सम्मान समारोह

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व विधायक हेमंत खण्डेलवाल करेंगे 'मुख्यमंत्री हॉकी कप' का शुभारंभ : मानसिंह यादव

भोपाल। भारतीय जनता पार्टी खेल प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक श्री मानसिंह यादव ने बुधवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में पत्रकार-वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि खेल प्रकोष्ठ द्वारा राष्ट्रीय खेल दिवस एवं हॉकी के महानायक मेजर ध्यानचंद जी की जयंती के अवसर पर 29 अगस्त को भोपाल के अरेरा क्लब के पास स्थित स्थित ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम में 'मुख्यमंत्री हॉकी कप' का आयोजन किया जाएगा। इसमें प्रदेश की चार सर्वश्रेष्ठ पुरुष एवं महिला हॉकी टीमों के बीच मुकाबले होंगे। उन्होंने बताया कि हॉकी के मुकाबले सुबह 10 बजे से प्रारंभ होकर शाम 5 बजे तक चलेंगे। 'मुख्यमंत्री हॉकी कप' का

शुभारंभ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व विधायक श्री हेमंत खण्डेलवाल करेंगे। इस अवसर पर प्रदेश उपाध्यक्ष श्री शैलेन्द्र बरुआ, प्रदेश महामंत्री श्री राहुल कोठारी एवं राष्ट्रीय मीडिया सह प्रभारी श्री आशीष उषा अग्रवाल सहित पार्टी के वरिष्ठ नेतागण एवं पदाधिकारी उपस्थित रहेंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त को लाल किले से देश के प्रतिभाशाली बच्चों की खेल प्रतिभा को सामने लाने की बात कही थी और इसका उद्देश्य कम उम्र की खेल प्रतिभाओं की पहचान कर उन्हें आवश्यक प्रशिक्षण एवं सुविधाएं उपलब्ध कराना है।

प्रदेश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों का होगा सम्मान- भाजपा खेल प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक श्री मानसिंह यादव ने कहा कि 29 अगस्त को शाम 6 बजे से अपेक्स बैंक समन्वय भवन, न्यू मार्केट, भोपाल में खिलाड़ी सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा। समारोह में मध्यप्रदेश के उन खिलाड़ियों एवं खेल गुरुओं का सम्मान किया जाएगा, जिन्होंने राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश और देश का नाम रोशन किया है। समारोह में केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाले खेल रत्न, द्रोणाचार्य एवं अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित मध्यप्रदेश के खिलाड़ियों के साथ ही प्रदेश सरकार के विश्वामित्र, विक्रम एवं एकलव्य पुरस्कार प्राप्त खिलाड़ियों का भी सम्मान किया जाएगा।

'राम राजा भी है, राम तपस्वी भी है'

चार साल की यतिका से घुटनों पर बैठ कवि कुमार विश्वास ने सुना रामगीत, कहा- क्यूट हो तुम

उज्जैन (नप्र)। मशहूर कवि कुमार विश्वास दो दिन पहले उज्जैन स्थित महाकाल मंदिर में दर्शन करने गए थे। उज्जैन से लौटते वक्त जब वह इंदौर एयरपोर्ट पर पहुंचे तो चार साल की यतिका उनके सामने आई और रामगीत सुनाने लगी। उसकी मधुर आवाजों को सुनने के लिए कवि कुमार विश्वास घुटनों पर बैठ गए।

यतिका गांधी सुनाने लगी रामगीत- दरअसल, कुमार विश्वास जब उज्जैन से लौट रहे थे, तब एयरपोर्ट पर गाड़ी से उतरते ही चार साल की यतिका गांधी उनके सामने पहुंच गई। इसके बाद यतिका गांधी उन्हें राम गीत सुनाने लगी। यतिका उन्हें सुना रही थी कि राम राजा भी है, राम तपस्वी भी है...।

घुटनों पर बैठ गए कुमार विश्वास- यतिका की आवाजों को सुनने और प्यार देने के लिए कुमार विश्वास घुटनों पर बैठ गए। उसकी आवाज में रामगीत सुनने लगे। इसके साथ ही उन्होंने उसके साथ सुर-सुर में भी मिलाया है। साथ ही उसकी आवाज की तारीफ की है।

कितना सुंदर गाया आपने- कवि कुमार विश्वास ने गीत सुनने के बाद बच्ची से पूछा कि आपका नाम क्या है। उसने अपना नाम यतिका गांधी बताया। इसके बाद

कुमार विश्वास ने कहा कि आपने कितना सुंदर गाया है। मैं भी सिखूंगा, इसे मुझे आता नहीं है। फिर यतिका को दुलारते हुए कहा कि बहुत क्यूट हो आप।

लोग कर रहे हैं तारीफ- वहीं, इंदौर एयरपोर्ट पर कुमार विश्वास के इस सहज अंदाज की तारीफ हो रही है। वह यतिका को देखकर रुक गए और गीत को ध्यान से सुना है। अब यतिका का यह वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है।